

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1973

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

## विषय सूची

बुधवार, 7 मार्च, 1973

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45 के अधीन पटल पर रखे गए	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)27
कार्य मन्त्रणा समिति का दिवतीय प्रतिवेदन	(3)32
पटल पर पुनः रखे जाने कागज—पत्र	(3)34
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)34

# हरियाणा विधान सभा

बधुवार, 7 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,

सैक्टर.1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9 : 30 बजे हुई। अध्यक्ष

(श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

## तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्नोंत्तर काल।

### **Pending Challans**

**\*181. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state total number of cases of incomplete challans lying pending with the police authorities as on 1<sup>st</sup> April, 1972 in Jind District?

**Home Minister (Sh. K.L. Poswal):** No incomplete challan was pending with police in Jind District on 1<sup>st</sup> April, 1972. However, 221 cases were under investigation in this district on 1<sup>st</sup> April, 1972, as per statement attached.

**Crime statement from 1.4.71 to 31.3.72 of  
District Jind.**

Under the Indian Penal Code.

Sr. No.	Head	No. of cases registered	No. of cases pending on 1-4-72
1.	Murder	8	1
2.	Culpable Homicide	4	-
3.	Attempt to murder	8	-
4.	Hurt	54	7
5.	Rioting	9	-
6.	Kidnapping	4	1
7.	Assault on Public Servants	13	4
8.	Dacoity	-	-
9.	Rabbery	3	-
10.	Burglary	89	18
11.	Theft	119	22
12.	Receiving stolen property	26	3
13.	U/S447/449/409, IPC	8	-
14.	Motor Accidents	33	12
15.	U/s 447/449, IPC	8	12

16.	U/s 406/409, IPC	16	17 (one case relates to the years 1970-71)
17.	Cheating	10	2
18.	U/S 354, IPC	6	
19.	U/S 376, IPC	1	
20,	Misc.	24	3
	<b>Total</b>	436	90
<b>Under Local And Special Laws.</b>			
21.	Excise Act.	500	84
22.	Opium Act.	109	30
23.	Arms Act	37	4
24.	Gambling Act.	90	3
25.	7/10/55	4	1
26.	Untouchability offences Act	2	2
27.	102/121 Rly Act	17	6
28.	5(2) 47 PC Act	1	1
	<b>Total</b>	761	131

**चौधरी दल सिंह:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उन्होंने जो 221 पैडिंग केसिज बताये है, वे किस नौइयत के है और उनकी अब क्या पोजीशन है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** इसमें पोजीशन यह है कि 114 केसिज तो वहे है जो एक्साइज ऐंड ओपियम ऐक्ट के है जिनमें कैमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट का इन्तजार है। 107 ऐसे है जो कम्पीलकेटिड नेचर के है और जो सी.आई.ए. के पास अंडर इन्वैस्टीगेशन है, कुछ की इन्वैस्टीगेशन की भी है और कुछ अकाउट्स बुक्स बगैरा देखने और गवाह वगैरा जो बाहर के है, उनकी पूछताछ बाकी है।

**श्री अध्यक्ष:** इनमें चोरी के कितने केस है?

**श्री के.एल.पोसवाल:** सिर्फ 22 है और वे जिला जींद के है।

**चौधरी रिजक राम:** वजीर साहब ने यह जो पैडिंग केसिज बताये है इनमे पुराने से पुराने कितने केस पैडिंग है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** यह एक साल की रिपोर्ट हैं

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या वजीर साहब तायेगे कि इनके अलावा और किनिं केसिज है जिनको दर्ज नहीं किया गया है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** ऐसा कोई नहीं हैं

**चौधरी दल सिंह:** क्या वजीर साहब बतायेगे कि यह जो आपने केसिज पैडिंग बताये है और कहा है कि अंडर इन्वैस्टीगेशन है तो इनकम्प्लीट और अंडर इन्वैस्टीगेशन में क्या अंतर है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** आजकल इनकम्प्लीट चालान पेश ही नहीं किया जाता, कम्प्लीटर चालान ही पेश किया जाता है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** वजीर साहब ने बताया है कि 107 केस कम्प्लीकेटिड नेचर के है जिनकी इन्वैस्टीगेशन जारी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनका एफ.आई.आर. कब दर्ज किया गया था?

**श्री के.एल. पोसवाल:** यह एक साल की रिपोर्ट है और एक साल से केस पैडिंग है।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** वजीर साहब ने जो यह केस बताये है इनमें 107६151 के कितने केस है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** सवाल में हय बात पूछी नहीं गई थी सिर्फ पैडिंग के बारे में पूछा गया था आरे यह बता दिया है।

**चौधरी फूल चन्द (रोहट):** क्या वजीर साहब बतायेगे कि पैडिंग केसिज की म्याद कितनी है और कब तक वह पैडिंग रह सकते है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** जब तक इन्वैस्टीगेशन पूरी नह हो जाये।

**चौधरी दल सिंह:** मैंने सवाल किया था 'ऐज आन फर्स्ट अप्रैल, 1972' और इसका मतलब है कि उस दिन तक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले साल के कितने हैं और उस साल के कितने हैं?

**श्री के.एल. पोसवाल:** आपने तारीख की इनफरमेशन मांगी है ता हमने सारे साल की दे दी है वरना हम 6 महीने की भी दे सकते थे।

**मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल):** यह केसिज 1.4.71 के बाद के है।

**चौधरी पीर चन्द:** अध्यक्ष महोदय यह जो केसिज है क्या इनके बारे में कोई ऐसी प्रोपोजल भी है कि उनको वापिस लेना है क्योंकि किसी केसी में दिक्कत हो सकती है या वह गलत दर्ज हो गया हो और उसको आप सही न समझते हो?

**श्री के.एल. पोसवाल:** किसी केस में अगर इन्वैस्टीगेशन में साबित हो जाये कि केस बनता नहीं है या गलत बना है तो उसे वापिस भी ले लेते हैं।

**चौधरी रिजक राम:** अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि यह 1.4.71 से 1.4.72 तक की लिस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे केसिज भी हैं जो 1.4.71 से पहले के दर्ज किये हो और उनकी इन्वैस्टीगेशन पैडिंग हो?



चौधरी बंसी लाल: सवाल में यह दे नहीं रखा है।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या इनमें से कुछ केस वापिस लिये गये है ओर अगर लिये गये है तो कितने लिये गये है?

श्री के.एल. पोसवाल: यह बात सवाल मे पूछी नहीं गई है।

श्री अमर सिंह: क्या यह हकीकत नहीं है कि बहुत सारे केस दो साल पहले के पैडिंग पड़े हुये है? यह जो 114 केस एक्साइज एक्ट के बताये गये है कि कैमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट का इंतजार है तो यह रिपोर्ट तो उसे 6 महीने के अन्दर देनी होती है लेकिन फिर भी यह कैसे इस बिना पर पैडिंग पड़े है?

श्री के.एल. पोसवाल: बाज दफा 6 महीने में यह रिपोर्ट आ नहीं पाती है।

चौधरी शिवराम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेगे कि केस वापिस लेने का क्या प्रोजीजर है? क्या ये केस डिसिट्रक्ट अथोरिटीज वापिस ले सकती है या सरकार से पूछना पड़ता है?

श्री के.एल. पोसवाल: डी.सी. वापिस ले सकता है।

**E.S.I Dispensary in Sarvan Village of Faridabad  
Block**

**\*184. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) The Total number of rooms in the E.S.I. Dispensary opened recently at village Saran of Faridabad block;

(b) The monthly rent being paid for the above dispensary; and

(c) The name of the owner of the building of above dispensary?

**Home Minister (Sh. K.L. Poswal):**

(a) 6 Rooms.

(b) No rent is to be paid. The House is to be vacated by 15<sup>th</sup> March, 1973. The owner, Shrimati Sharda Rani, has agreed not to charge any rent.

(c) Shrimati Sharda Rani, Minister of State for Home and Health.

**श्री के.एन. गुलाटी:** मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह यह हाउस वर्कर्स के इंट्रैस्ट में तब तक खाली नहीं करेगे जब तक कि दूसरी जगह नहीं मिलती है?

**श्री के.एल. पोसवाल:** इसमें बात ऐसी है कि यह बिल्डिंग हमने उनसे रिक्वेस्ट करके ली थी। देने से पहले उनहोंने यह उन्होंने यह कहा था कि पहले चीफ मिनिस्टर साहस से पूछ लूँ कि बिल्डिंग दे सकती हूँ या नहीं। उनसे पूछा गया था और

उन्होंने रजामन्दी दे दी कि वह रैट चार्ज नहीं करेंगी। उन्होनत तक कहा कि 30 मार्च तक यह खाली कर देनी चाहिए। कोशिश तो हम करेंगे और रिक्वैस्ट करेंगे कि जब तक दूसरी जगह नहीं मिलती उसे खाली न कराये लेकिन हम उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं।

### **Liquor Shops**

**\*194. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Development be pleased to state the total number of shops of country liquor and together with the total number of such shops located in rural areas and urban areas, separately?

Development Minister (Sh. Shyam Chand):

Total number of Country liquor Shops	226
(i) Shops in rural areas	180
(ii) Shops in urban areas	86
Total number of I.M.F.L Shops	244
(i) Shops in rural areas	22
(ii) Shops in urban areas	222

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इससे कितना रैवेन्यू सालाना सरकार को आ रहा है?

**Sh. Shyam Chand:** This year, it is over eleven crores.

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बतायेगे क देसी और अंग्रेजी दोनों शराबों की अलहदा-अलहदा कितनी बोतले सालाना खपत हो रही है?

**Sh. Shyam Chand:** So far as country liquor is concerned, it is 45 lakh proved litres. For I.M.F.L. we do not have any record because it is sold in the bars also.

**राव निहाल सिंह:** क्या वजीर साहब तायेगे कि यह जो नम्बर इनहोने बताया है इसमें हरिजनों के लिए क्या रिजर्वेशन है? .....(हंसी).....

**श्री अध्यक्ष:** क्या पीने की या बेचने की? (हंसी)

**आवाजे:** पीने की।

**श्री श्याम चन्द:** हरिजनों ने पीनी शुरू नहीं की है।

**श्री हरि सिंह:** क्या वजीर साहब बतायेगे क शराब पीने से क्या लाभ होता है?

**Sh. Shyam Chand:** Sir, only Bacchus, the God wine, in Greek mythology, can tell the hon. Member about the advantges of drinking. But, one thing I can tell from my observations of the ways of those who drink is that when wine goes in truth comes out.

**श्री ओम प्रकाश गर्ग:** क्या वजीर साहब बतायेगे कि अंग्रेजी और देसी शराब की दुकाने देने का क्या तरीका है?

**Sh. Shyam Chand:** For country liquor, there is an open auction.

**श्री अध्यक्ष:** क्या गर्ग साहब के लिए कोई रिसायत हो सकती है?.....(हंसी).....

**श्री श्याम चन्द:** यह तो उस कैटरी में नहीं आते हैं।

**चौधरी पीर चन्द:** क्या वजीर साहब बतायेगे कि यह शराब जो लै इसे बन्द करके किसी और तरीके से रैवेन्यू वसूल करेगे क्योंकि शराब जो है इससे हरियाणा के अन्दर.....

**श्री अध्यक्ष:** आप सीधा सवाल क्यों नहीं करते कि क्या सरकार प्रोहिबिशन करेगी या नहीं?

**चौधरी पीर चन्द:** क्या सरकार इस शराब को बन्द करना चाहती है?

**श्री श्याम चन्द:** यह अंडर कन्सिड्रेशन है।

**चौधरी फूल चन्द (रोहट):** क्या वजीर साहब बतायेगे कि सरकार ने शराब की दुकानें खोलने के रूल बना रखे हैं तो क्या पीने के रूल भी बना रखे हैं कितनी पीनी चाहिये?

श्री श्याम चन्द: पीने के तो नहीं लेकिन खरीदने के है कि एक बोतल से ज्यादा नहीं खरीद सकते।

चौधरी राम लाल वधवा: मंत्री महोदय ने जो स्टैटमेंट दी है उसे मुताबिक देहातों में देसी शराब की दुकानें ज्यादा है और अंग्रेजी शराब की दुकानें कम है। क्या मंत्री महोदय इसका कारण बतायेगे कि ऐसा क्यों है?

श्री श्याम चन्द: कारण यह है कि शहरों में लोग अंग्रेजी शराब ज्यादा पीते है, इसलिए शहरों में दुकाने ज्यादा है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि वे कौन-कौन सी ऐसी जगहे है जहां पर शराब की दुकानें नहीं खोली जाती, किन-किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है?

**Sh. Shyam Chand:** Like schools and other religious insitiutions. If the schools are for boys then the distance should be 100 meters. If these are co-educational, then the distance should be 150 metres. In the case of religious temples, the distance shoudl be 100 metres and as for bus stands, it should be 100 metres.

चौधरी शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे की जिस गांव में सरकार ने शराब की दुकान खोली है और उस गांव की पंचायत सा सारी आबदी उस दुकान को बन्द करवाने की इच्छुक है तो क्या सरकार उस दुकान को बन्द करेगी? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके अनुसार दुकान बदली जा सके?

**श्री श्याम चन्द:** अगर पंचायत रैजोल्यूशन पास करती है तो हम दुकान नहीं खोलगे। अगर सरपंच अपनी शराब निकलाता हहो तो हम जरूर खोलगे।

**श्री के.एन. गुलाटी:** जैसा क मंत्री महोदय ने बताया है कि बस स्टैण्ड के नजदीक 100 मीटर तक कोई शराब का ठेका नहीं खोला जायेगा। क्या मंत्री महोदय फरीदाबाद के बस-स्टैण्ड के पास और गुडगांव डी.टी.यू. बस स्टैण्ड के नजदीक जो शराब के अड्डे खुले हुये है उनकों बन्द करने पर विचार करेगे?

**श्री श्याम चन्द:** अगर ऐसी बात होगी तो शिफ्ट कर देगे।

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, सरकार ने मिर्जापूर गांव में शराब का ठेका खोला है और उस गांव की पंचायत से रैजोल्यूशन पास होकर आया है कि वहां पर गर्ल्स स्कूल के साथ ठेका खुला हुआ है। क्या मंत्री महोदय उस ठेके को चैक करने की कृपा करेगे कि वह गर्ल्स स्कूल के साथ नहीं होना चाहिये?

**श्री ओम प्रकाश गर्ग:** अगर मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाई जाये कि फला ठेकेदार शरायत के मुताबिक ठेका नहीं चलाते तो क्या मंत्री महोदय उस ठेके को वहां से हटा लेंगे?

**श्री श्याम चन्द:** जरूर हटा लेगे।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** दो साल से शराब की दुकाने लगातार बढ़ती जा रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि गांधी शताब्दी और 25 वे स्वतन्त्रता वर्ष की साल गिरह के उपलक्ष में दुकाने बढ़ाई जा रही है?

**Sh. Shyam Chand:** Actually, we want to curb the monopolistic tendency in this business. अगर एक आदमी नाजायज फायदा उठाता है तो उससे बेहतर है कि सरकार फायदा उठाये ज्यादा दुकाने खोलने से प्राईस कम होगी और शराब अच्छी क्वालिटी की मिलेगी।

**शाह हकूमत राय:** स्पीकर साहब, जहां धार्मिक स्थान या शिक्षा संस्थायें हैं वहां शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिये लेकिन सरकार वहां भी खोल रही है। सरकार ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पानीपत, जो जी.टी.रोड़, पर वाक्या है, के पास जो ठेका खोला है, क्या सरकार इसको वहां से हटा देगी?

**Sh. Shyam Chand:** Not only for the hon. Member Sh Hakuat Rai Ji but any body can make a complaint and that will be looked into.

**Overseers, S.D.Os. Suspended and Charge sheeted  
in the state**

**\*198 Sh. Amar Singh:** Will the Minister for revenue be pleased to state—



(a) The Total number of Overseers and S.D.Os. working under the state Crash Programme of Roads in the State from June 1972 to date; and

(b) The Division-wise name of Overseers and S.D.Os. referred to in part (a) above who were suspended and charge-sheeted together with the reasons thereof?

**Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):**

(a)	(i) Wholly for Crash Programme.	
	Sub-Divisional Engineers	26
	Sectional Officers	258
(ii)	Partly on Building construction and partly on Roads construction	
	Sub-Divisional Engineers	92
	Sectional Officers	170
(iii)	Partly on maintenace and partly on Road construction	
	Sub-Divisional Engineers	6
(b)	(i) Sh. P.C. Malik Ambala Provl. Sub-Divisional No. 1 Engineer	Bichpuri approach aroad under construction was not according to correct longitudinal profile and there was defective consolidation of

			metalling. He is being charge-sheeted.
	(ii) Sh. Ram Chander Sectional Officer	Do	Do
	(iii) Sh. V.P., Katyal, Sub-Divisional Engineer	Hansi Prov. Division	On account of making advance payment to Sh. Hawa Singh, Brick Kilan owner, Dhanana on 3 <sup>rd</sup> August, 1971 without taking delivery of the bricks. He is being charge-sheeted.
	(iv) Sh. Mam Chand, Sectional Officer.	Ambala Provl. Division No. II	It was found on the construction of road from Ambala Hissar to village Tabra that work was being done without adequate supervision and control. He is bieng charge-sheeted.

श्री अमर सिंह: क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बतायेगे कि उन्होंने मेरे सवाल के पार्ट 'ए' के उत्तर में जो तीन पार्टस में जवाब दिया कि—

- (i) Wholly for crash programme.
- (ii) Partly on Building construction.
- (iii) Partly on maintenance and partly on Road construction.

दो एस.डी.ओ. और ओवरसियर जो चार्जशीट हुये है, क्या ये पार्टली कैशी प्रोग्राम के काम लगाये गये थे या किसी और विग में काम करते थे?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** As for Sh. P.C. Malik, Sub-Divisional Engineer, the Chief Engineer inspected the work of construction of the Bichpuri approach road and it was found that the construction was not according to correct longitudinal profile and there was defective consolidaton. This is regarding crash programme of roads. So was the case in respect of Sh. Ram Chander, Sectional Officer. As for Sh. V.P. Dathya, Sub-Divisional Engineer, he issued a cheque to a contractor without taking delivery of the bricks. This was also under crach programme of roads.

**Ch. Phool Chand (Rohat):** May I know from the Hon'ble Minister as to what is the suspension perioad for which an employee can be kept?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** No specific period is prescribed. But Government tries to expedite action after charge sheeting the employee concerned.

**चौधरी चांद राम:** क्रैश प्रोग्राम अब बन्द कर दिया गया है तो क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इस प्रौग्राम को पूरा करने के

लिये जो स्टाफ लगाया गया था वह अब भी लगा हुआ है या नहीं? क्या यह स्टाफ अब भी स्टेट के ऊपर बोझ बना हुआ है या हटा दिया गया है?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** The establishment in P.W.D is sanctioned on the basis of work-load to be carried out in a particular year. During 1972-73 this work-load after budgetary cuts is of the order of Rs. 21 crores for civil works only after deducting establishment and electrical and mechanical works. The work-load norm for a civil Division is about Rs. 50 Lacs. However, in our state, lot of work like most of the earth work, consolidation, taring, carpet work and most of reperi works are done departmentally. Also allowance has o be given for maintenance works being equated about 2-2 ½ times for calculating the work-load.

As for the crach programme, it has been slowed down after June, 1972. A lot of bills have to be prepared and contracts finalised. In addition, a large number of detailed estimates have to be technically sanctioned by the field staff. Therefore, the staff employed for the crach programme has not been removed so far.

**चौधरी चांद राम:** मंत्री महोदय ने कहा है कि बिल तैयार करने है। बिल तैयार करने में कितना अर्सा लगता है? क्या इसके बाद इस स्टाफ को हटायेंगे या काम पर ही लगे रहने देंगे?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** The Government has taken a decision to connect all the village roads by the 26<sup>th</sup> of January, 1973. But in view of the instructions from the

central Government, we has to slow it down after the month of June, 1972, because attentin was diverted towards irrigation and electricity.

**श्री अमर सिंह:** क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि 30 जून, 1972 के बाद क्रैश प्रोग्राम बन्द हो गया था और जो चैक वगैरहा पहले ही बन चुके थे, बाद में डिस-ओन हुये है?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** It is incorrect to suggest that the work of crach programme has been totally stopped. It has been only slowed down. The question of cheques being dishonoured does not arise. Regualr payment are bing made.

**चौधरी शिव राम वर्मा:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने खुद ही कहा है कि 26 जनवरी, 1973 तक हरियाणा के हर गांव को सड़क से मिलाने का जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक केवल 60 परसैन्ट के लगभग गांव सड़कों से मिले है। क्या वे बतायेगे कि यह प्रोग्राम कब तक पूरा करने की आशा की जाये?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** It all depends upon the availability of funds. As I have already stated, it has only been slowed down and not stopped.

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बतलायेगे कि अगले साल में कितने फंड्ज है और कितने रोड्ज कम्पलीट हो जायेगे?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** Well, you will get details in the Budget which will be presented on the 9<sup>th</sup>.

**चौधरी रिजक राम:** क्या वजीर साहब फरमायेगे क जिस वक्त जून, 1972 में यह काम स्लों डाऊन किया गया उस वक्त कितनी डेली वेजिज पर काम करने वाली लेबर लगी थी? क्या उनको अब भी रखा हुआ है या हटा दिया गया हे? इसी तरह से बाकी टैक्नीकल स्टाफ की भी पोजीशन बताने की वे कृपा करनेगे?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** Mr. Speaker, sir, this supplementary does not arise out of this question The Hon'able Member may give a separate notice and I will supply the requisite information.

**राव बंसी सिंह:** स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, जब नारनौल के दौरे पर गये थे तो एक एग्जैटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था। क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि आज वह केस किस पोजीशन में है?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** One XEN, one S.D.O. and two sectional officers are still under suspension. When I visited Narnaul used. I took samples of the material being used e.g. bricks etc., at the site or works i.e. Hospital and Godown. It was on the basis of my personal information that it was decided to take action against these officers. They are being charge sheeted.

**चौधरी दल सिंह:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि वह कौन सी सड़क है जिसके ऊपर आपका अच्छा मैटीरियल लगा हुआ है?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** Mr. Speaker, the Hon'able Member should believe me when I say that on all roads good material has been used.

**श्री अमर सिंह:** स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि दो एस.डी.ओज. और दो ओवरसीयर्ज ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐलीगेशन है कि वे मैटीरियल ठीक नहीं लगा रहे थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि इन चारों के खिलाफ कितना अमाउंट इनबोलड है?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** so far as the suspension of Sh. P.C. Malik, S.D.E. is concerned, it does not involve any amount. So is the case of sectional officer attached with him. So far as the suspension of Sh. V.P. Katyal, S.D.E. is concerned, he issued a cheque for Rs. 5,119 to Sh. Hawa Singh, brick-Kiln owner, Dhanana on 3<sup>rd</sup> August, 1971 without taking delivery of the bricks. As the Brick-kiln owner did not supply bricks, the Sub-Divisional Engineer lodged a complaint with Police station Mundhal. The Police did not intervene and they held it to be a case of civil nature. The matter then came to the notice of the superintending Engineer who made a report to the Chief Engineer. The Chief Engineer recommended to Government suspension of the officer, which was done in December, 1972. The charge sheet is with the Government for signatures. As per latest position, some bricks have been

supplied and some payment has been recovered from other dues of the brick-kiln owner and now only Rs. 186 remains to be recovered.

During further investigation by the Department it has come to notice that this officer has been making other advance payments for other cases of bricks, hume pipes and soling to the extent of Rs. 73,129. Here also the efforts are being made by the superintending Engineer to recover the payments. So far a sum of about Rs. 22,500 has been adjusted and recovered.

**मलिक सतराम दास बत्तरा:** क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जहां अभी बहुत सारा मैटीरियल पड़ा हुआ है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से काम रूका पड़ा है। उन जगहों को पैसा आने के बाद टौप प्रायोरिटी दी जायेगी?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** Top priority will be given to the roads where soling and wearing has been done, tarring is to be done and where material is lying. Those roads will be completed.

**चौधरी फूल सिंह कटारिया:** क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि वर्तमान मंहगाई को देखते हुये मजदूरों की तरखाह बढ़ाने का मामला सरकार के जेर गौर है?

**Pandit Chiranji Lal Sharma:** It is a matter of policy. You will find it in the Budget.





and road construction

6

**Total**

**124**

As for Sectional officers, there are 780 sectional officers (Civil) in this department. Out of these 105 sectional officers are meant for National Highways works, while 29 are engaged on survey works, thereby leaving a balance of 646 sectional officers engaged as under:-

(i) Purely roads works	258
(ii) Purely building works	72
(iii) Doing mixed roads and building works	170
(iv) Doing maintenance works	146
<b>Total</b>	<b>646</b>

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, थोड़ी पोजीशन अगर मैं क्लीयर कर दूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो तीन आनरेबल मैम्बर साहिबान, ने यह पूछा कि सड़के जो इस वक्त तक बन जानी चाहिये थी उनका पोस्टपोन क्यों किया गया? इनको पोस्टपोन करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमने बाद में प्रायरिटी चेंज कर दी। पहले हमारा इरादा था कि सबसे पहले सड़के बना दें लेकिन बाद में सड़कों की बजाय प्रायरिटी हमने नहरी पानी को, बिजली को ओर पीने के पानी को दी। जो 13-14 करोड़ रूपया आँगमैटेशन कैनल पर हमने खर्च किया उसका प्रोविजन जब हमने चौथा पांच साला प्लान बनाया हमारी

प्लान में नहीं था। जूई कैनल, इंदिरा गांधी कैनल और बीरेन्द्र नारायण चक्रवती कैनल का जिक्र हमारी प्लान में नहीं था। ज्यादा अनाज पैदा करने के लिये, ज्यादा ट्यूबवैल्ज लगाने के लिये, बिजली की लाईनें ज्यादा खींचने के लिये, पावन जैनरेशन ज्यादा करने के लिये, ज्यादा खर्च बजाय सड़कों पर करने के हमने इरीगेशन, पावर और पीने के पानी की सुविधाए उपलब्ध कराने की तरफ डायवर्ट कर दिया।

स्पीकर साहब, चौधरी रिजक राम जी ने जो पूछा कि क्या बाद में इंजीनियरिंग खाली पेमेंट करते रहे उसके बारे में यह अर्ज है कि पहले वे बहुत ज्यादा ओवर-वर्कड थे। उनके ऊपर वर्क-लोड 100 परसेंट की बजाय 200-300 परसेंट था। इसके बाद काम नॉर्मल हो गया। वैसे तो अब भी नॉर्मल काम से ज्यादा काम उनके पास हैं

जहां तक, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, उन सड़कों का संबंध है, जहां मैटीरियल पड़ा हुआ है, उनको जैसा कि आनरेबल मंत्री महोदय ने कहा है, हम तरजीह देंगे।

### **Tube wells in District Karnal**

**\*213. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) Whether the Government is aware of the fact that at some places the pumping sets of farmers have stopped lifting water in District Karnal;

(b) If so, the measures proposed to be adopted to regain the position;

(c) The total number of Government tube wells installed in District Karnal Since 1<sup>st</sup> April, 1972; and

(d) The quantity of water that will be received from the tube wells mentioned in part (c) above along with the area of land which will be irrigated thereby, together with the benefit to be accrued as compared to the loss to be sustained in District Karnal?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) & (b) Yes. In a limited area along Narwana Branch between rivulets of Tangari and Markanda, a few private tube wells have been affected by lowering of sub-soil water. The level has gone down by about 15 feet since 1957 to June, 1972 on account of poor rainfall and construction of protection bunds and diversion bunds between Tangri and Markanda. The sub-soil water level is likely to improve with normal rains. The Sub-soil water level is likely to improve with normal rains. It is also proposed to do artificial re-charge of the ground water. The owners of the affected tube wells can also lower their pump settings in order to run the tube wells. In the meantime they have been permitted to take water from the Augmentation tube wells so that their crops are not damaged.

(c) Since 1<sup>st</sup> April, 1972, 281 State Tube wells have been installed in Karnal District along new Augmentation canal, Narwana Branch, NBK Link & Delhi Branch.

(d) The capacity of these tube wells is 700 cusecs and they are capable of Irrigating 1.5 lakh acres of land. This can yield an additional production of over one lakh tones of food grain per annum. No loss has been sustained in District Karnal on account of these tube wells.

**चौधरी शिव राम वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले 'हां' कहा है लेकिन उसके बाद ऐक्सप्लेन करते वक्त टांगरी और मारकण्डा के आसपास के किसानों के ट्यूबवैल्ज का जिक्र किया है। इसके अलावा भी दूसरे इलाकों में किसानों के ट्यूबवैल्ज को पानी देना छोड़ गये है। ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात का पता नहीं है। क्या सरकार इस बात का पता कराने की कोशिश करेगी?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा:** 1967 में पांच फुट पानी नीचे चला गयाथा। 1967 से 1971 तक पांच फुट पानी और नीचे चला गया था। जब औगमैटेशन कैनल बनी उससे पहले पन्द्रह फुट पानी बारिश कम होने की वजह से नीचे जा चुका था। हमारे ट्यूबवैल्ज की वजह से पानी लगभग चार इंच से लेकर दस इंच स ज्यादा तक नीचे नहीं गया है।

**चौधरी चांद राम:** क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि औगमैटेशन ट्यूबवैल्ज के कारण पानी का लैबल नीचे गया है?

**श्री अध्यक्ष:** ये तो वे बता चुके हैं कि चार से लेकर दस इंच तक नीचे गया है।

**चौधरी चांद राम:** क्या इस सिलसिल में इंद्री और रादौर के एरिया के जमींदारों की शिकायतें सरकार के पास आई हैं?.....(विधन).....

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा:** अक्टूबर सन् 1972 में हमने इन ट्यूबवैल्ज को चालू किया हैं अगर पहले ही इन ट्यूबवैल्ज का पानी नीचे चला गया हो तो हमारा क्या गुनाह है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि औगमैटेशन कैनल चालू करने के बाद पानी का स्तर कितना नीचे गया है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा:** औगमैटेशन कैनल का कोई अफैक्ट नहीं हुआ है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि औगमैटेशन कैनल चालू करने के बाद पानी का स्तर कितना नीचे गया है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा:** औगमैटेशन कैनल का कोई अफैक्ट नहीं हुआ है।

**चौधरी रिजक राम:** क्या वजीर साहब बतायेगे कि स्टेट में कितने प्राइवेट ट्यूबवैल्ज के पानी का स्तर नीचे को चला गया है, उनकी कुल कितनी तादाद है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा:** 14 ट्यूबवैल्ज है, जिनका पानी कम हुआ है। उनके लिए एम.आई.टी.सी. ने फैसला किया है कि वे जितना भी पानी लेना चाहे, ले सकते हैं।

**श्री ओम प्रकाश गर्ग:** क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ने कितने नहर के साथ-साथ और कितने दूसरे ट्यूबवैल्ज लगाये हैं?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा:** नरवाना ब्रांच में 100 ट्यूबवैल्ज एम.बी.के. लिंक पर भी 100, दिल्ली ब्रांच पर भी 100 और औगमैटेशन नहर पर 160 ट्यूबवैल्ज लगाये हैं। इकसे अलावा भाखड़ा मेन ब्रांच पर 100 लगाने जा रहे हैं।

**चौधरी रिजक राम:** क्या वजीर साहब बतायेगे कि स्टेट में जो ट्यूबवैल्ज लगाये जा रहे हैं। चाहे वे प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के हैं उनके बार में यह देखने में आया है कि वे इन डिसक्रिमिनेट तरीके पर लगाये जा रहे हैं? क्या सरकार की कोई तजवीज है कि इन ट्यूबवैल्ज को सैक्शन करने के लिए इनस्टालेशन करने के लिए कोई तरीका रेगलुट करेंगे कि इतने फासले पर दूसरा ट्यूबवैल्ज हो? क्या ऐसी पोजीशन भी आई है कि

प्राइवेट ट्यूबवैल लागने से गवर्नमेंट के ट्यूबवैलज बेकार हो गये हो?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा:** एक ट्यूबवैल दूसरे ट्यूबवैल से तकरीबन 1500 फुट के फासले पर लगाया जाता है। अगर कहीं पानी की कमी होने की शिकायत आई है तो एम. आई. टी. सी. यह कर रही है कि वहां सब-सायला को रिचार्ज कर रही है ताकि लोगों को नुकसान न हो।

**मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल):** चौधरी रिजक राम जी के प्वायंट को क्लैरिफाई कर दूं। कुछ जगह पर जब मैं टूर पर गा तो मेरे सामने भी यह बात आई है। ज्यादा नजदीक प्राइवेट ट्यूबवैलज लगने की ही शिकायत आई है। गवर्नमेंट ट्यूबवैलज तो एक लिमिट के अन्दर लगाये जाते हैं लेकिन प्राइवेट वाले लगा लेते हैं। उनको रैगुलेट करने की बात हमारे विचाराधीन है और उसको रैगुलेट करना भी जरूरी है। यह जो पानी नीचे गया जैसा कि आनरेबल मिनिस्टर ने बताया है कि इस औगमैटेशन कैनल के या इन ट्यूबवैलज का असर तो इसलिये नहीं हुआ कि यह औगमैटेशन कैनल तो चली ही अब है, उसे बाद का स्ट्रेटा तो किसी के पास है ही नहीं। हकीकत यह है कि पिछले कई साल का बारिश का सर्वे यह बताता है कि तीन-चार साल या पांच साल बारिश नॉर्मल रेंज से कम होती है, फिर अगले तीन-चार साल या पांच साल कुछ नॉर्मल से ज्यादा होती है। सन् 1957 से लेकर अब तक मारकण्डा और टांगरी के इलाके में जो बांध बनाये गये हैं



पलड के रोक देने से कि पानी जमीन में रिचार्ज नहीं हो ताता। तो अब उसका इलाज हमने यह सोचा है कि जो हार्ड क्ले नीचे है उस हार्ड क्ले से नीचे नॉर्मल रूटीन में पानी नहीं जाता उसको एम.आई.टी.सी. वाले अब बोर करके और उसमें मिट्टी डाल करके आर्टिफिशियली रिचार्ज करेंगे और पलड के पानी को उस तरफ को डाईवर्ट करेंगे ताकि नॉर्मली नीचे पानी मिलता रहे और जो एम.आई.टी.सी. के औगमेंटेशन ट्यूबवैल्ज हैं उनकी गहराई इतनी है कि वैसे भी इसको अफैक्ट नहीं करता।

प्राइवेट जो ट्यूबवैल्ज हैं उनकी तो गहराई है स्पीकर साहब 60 से 100 फुट तक सिर्फ गवर्नमेंट के जो दिल्ली ब्रांच, नरवाना ब्रांच, एम.बी.के. लिंक या औगमेंटेशन कैनल है उनमें से दिल्ली ब्रांच, नरवाना ब्रांच और एम.बी.के. ब्रांच पर तीन सौ से साढ़े चार सौ फुट तक की गहराई है और औगमेंटेशन कैनल पर चार सौ से लेकर एक हजार फुट तक की गहराई है। तो इन ट्यूबवैल्ज का वैसे भी प्राइवेट ट्यूबवैल्ज पर असर नहीं पड़ता, मगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसान अनजाने में, भोलेपन में एक दूसरे के नजदीक ट्यूबवैल्ज लगा करके बरबाद न हो जाये इसको रेगूलेट करना जरूरी है।

**चौधरी रिजक राम:** क्या चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात आयी है कि जो गवर्नमेंट की एम.आई.टी.सी. के ट्यूबवैल्ज हैं उनका जो कमान्ड एरिया है उसमें प्राइवेट

ट्यूबवैल्ज लगने की वजह से कई गवर्नमेंट के ट्यूबवैल्ज भी बेकार हुए हैं ?

**चौधरी बंसी लाल:** गवर्नमेंट ट्यूबवैल्ज खास मेरे नोटिस मे नहीं आये हैं। एक दो की बात मेरे नोटिस में आयी है। मैंने चैक करवाया तो ट्यूबवैल्ज ठीक काम कर रहे थे।

**श्रीमति लेखवती जैन:** क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि अम्बाला जिले में और खास तौर से अम्बाला कांस्टिच्युएँसी में कितने ट्यूबवैल्ज गवर्नमेंट ने लगाये हैं या लगाने जा रही है ?

**चौधरी बंसी लाल:** कांस्टिच्युएँसीवाइज हमारे पास कोई डिटेल नहीं होती।

**श्रीमति लेखवती जैन:** कम से कम यह तो बता दें कि उसकी मर्जी से अम्बाला जिले में कितने लगाये जा रहे हैं ?

**चौधरी बंसी लाल:** अम्बाला जिले में तो बहुत लग रहे हैं। सब जगह से ज्यादा लगाये जा रहे हैं। (हंसी)

**चौधरी रिजक राम:** ये तो कौन्ट एरिया का पूछ रही है। (हंसी)

**Total Buses with the Haryana Roadways**

**\*249. Ch. Brij Lal:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the total number of buses of Haryana Roadways in the State as on the 31<sup>st</sup> March, 1968 and 31<sup>st</sup> March, 1972, separately;

(b) the total number of buses added to the fleet in the year 1972-73; and

(c) the total number of buses which are likely to be added in the year 1973-74 ?

**Transport Minister (Col. Maha Singh):**

(a) No. of buses of Haryana Roadways:

(i) As on 31<sup>st</sup> March, 1968                      567

(ii) As on 31<sup>st</sup> March, 1972                      1217

(b) No. of buses added to the fleet during 1972-73 (upto January, 1973).    152

(c) No. of buses which are likely to be added in the 1973-74.    290

**चौधरी बृज लाल:** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में कुल कितनी बसों की आवश्यकता है और एक बस कितने किलोमीटर चलने पर कंडैम की जाती है ?

**कर्नल महा सिंह:** हरियाणा में बसों की काफी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बसें मिलें

लेकिन मैं यह भी साफ कर दूँ कि हमें रूपये की कोई दिक्कत नहीं है। कारखानों से हमें बसें नहीं मिल रही हैं। हम हर साल करीब करीब तीन सौ, चार सौ बसें ऐड करेंगे। इसके साथ ही 80—100 बसें रिप्लेस करते जाते हैं। बसों के कंडैमनेशन के लिए एक बोर्ड बना हुआ है वह कंडैम कर दे तो रिप्लेस कर दी जाती हैं।

**राव अभय सिंह:** क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि रिवाड़ी में बहुत खराब बसें चल रही हैं ? क्या इनकी हालत को ठीक रकने के लिये सरकार कोई स्टैप ले रही है ?

**श्री अध्यक्ष:** यह तो उन्होंने बतला दिया है। सरकार नई बसें लेने की कोशिश कर रही है लेकिन मैनुफैक्चरर्स से मिल नहीं रही हैं।

**कर्नल महा सिंह:** रिवाड़ी में इस महीने पांच नई बसें चलाई हैं। चालीस बसों की बाड़ी बिल्ट होकर आ रही है। आहिस्ता—आहिस्ता गुड़गांव—रिवाड़ी डिपो में बसें रिप्लेस कर दी जायेंगी।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो टोटल माइलेज है, उसके हिसाब से कितनी बसों की कमी है ?

**कर्नल महा सिंह:** जहां पर बसें नहीं चल सकतीं, क्योंकि सड़कें बन रही हैं, वहां पर जैसे कल भी बताया गया था,

टैम्पो के लिये हम लाईसेंस दे रहे हैं। जब सड़कें बन जायेंगी और हमारे पास बसें और आ जायेंगी तब टैम्पो बन्द कर दिये जायेंगे। फरवरी, 1973 तक हमारे पास 170 रिलीज्ड रूट्स थे लेकिन इनको लिबरलाईज करने के लिए, अभी इस महीने में ही हमने तादाद 325 कर दी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैम्पो मिल सकें।

**चौधरी फूल सिंह कटारिया:** क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो उनके पास नई बसें आ रही हैं, उनमें से झजझर तहसील और साल्हावास के हल्के लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए, जहां पर कि बहुत कम बसिज चल रही हैं, हिस्सा दिया जायेगा ?

**कर्मल महा सिंह:** झजझर और साल्हावास को भी उनका हक जरूर दिया जायेगा।

**चौधरी मनफूल सिंह:** क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि एक बस को आन-सर्विसेबल करार देने के लिए कितनी माइलेज चलने की जरूरत है ताकि उसको कन्डैम किया जा सके ?

**कर्मल महा सिंह:** जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इस बारे में कोई खास माइलेज लिमिट नहीं है। इस बारे में एक बोर्ड बना हुआ है जो सब बातों को विचार करने के पश्चात् कन्डैम करता है।

**मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल):** इस बारे में माईलेज की लिमिट नहीं है। बस की नॉर्मल ऐज 6 साल होती है।

**कर्मल महा सिंह:** हां जी, कम से कम 6 साल है। लेकिन अभी तक हमारे पास 6 साल से भी ज्यादा पुरानी बसें ठीक चल रही हैं और हम उनको चला रहे हैं।

**चौधरी दल सिंह:** क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि हरियाणा रोड़वेज की जो बसें हैं, जब सर्दी शुरू होती है, तब उनमें शीशे नहीं होते और लोगों को सर्दी लगती है और जब गर्मी शुरू होती है तब भी शीशे नहीं होते और लोगों को लू सताती है ?

**चौधरी बंसी लाल:** चौधरी दल सिंह पत्थर मार-मार कर तुड़वा देता है, तो हम क्या करें। (हंसी)

**चौधरी फूल चन्द (मुलाना):** क्या मंत्री महोदय के नोटिस में ऐसी कोई बात है कि बोर्ड ने कुछ बसिज को अन-सर्विसेबल करार दिया है और वे बसें उसके बाद भी रूट्स पर चल रही हैं जिससे लोगों को ब्रेक डाउन की दिक्कत पेश आ रही है ?

**कर्मल महा सिंह:** ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो तो मेरे नोटिस में लायें, मैं उसकी जांच करूंगा।

**चौधरी फूल चन्द (रोहट):** क्या वजीर साहब यह बतायेंगे कि एक बस की बौडी मुकम्मल होने पर कितनी लागत आती है और उसकी बौडी बनवाने के लिए क्या कोई स्टैन्डर्ड रेट्स मुकरर कर रखे हैं या टैन्डर मंगाए जाते हैं ?

**कर्नल महा सिंह:** हम चैसिज सारी की सारी दो तीन कंपनियों से ले लेते हैं, टाटा मसिडीज और ले-लैंड। उनकी कंपनियों के रेट्स अलग अलग हैं और बदलते रहते हैं।

**चौधरी फूल चन्द (रोहट):** एक बस को कम्पलीट होने में कितनी लागत आती है ?

**कर्नल महा सिंह:** इस वक्त हमें टाटा की बस 61 हजार में मिलती है और करीब 19 हजार रूपया उसकी बौडी बिल्डिंग में लगता है और ले-लैंड की बस हमें इस वक्त 66 हजार के करीब मिलती है और करीब उतना ही रूपया उसकी बौडी बिल्डिंग में लग जाता है जितना कि टाटा की बस पर लगता है।

**श्री उमेद सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एक बस की एनुअल इनक्म कितनी है ?

**कर्नल महा सिंह:** मार्च, 1972, में एक बस की एवरेज एनुअल इनक्म 20 हजार रूपये से कुछ ज्यादा थी।

**लाला रूलिया राम:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि हरियाणा के अन्दर चण्डीगढ़ डिपो, करनाल डिपो या कौन सा ऐसा डिपो है जिसकी आमदनी सबसे ज्यादा है ?

**कर्मल महा सिंह:** इस बारे में पोजीशन यह है कि कभी कोई डिपो आगे बढ़ जाता है तो कभी कोई। बराबर यह काम चलता रहता है। जिन डिपुओं में लम्बे रूट्स ज्यादा होते हैं, वहां ज्यादा अमादनी होती है।

**श्री ओम प्रकाश गर्ग:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, जैसे कि चण्डीगढ़ और दिल्ली के बीच नाईट सर्विस चलाई है, उसी तरह से हरियाणा के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी सर्विस चलाने का क्या सरकार कोई विचार रखती है ?

**कर्मल महा सिंह:** जी हां, यमुनानगर से अभी एक और सर्विस शुरू कर दी है और इसी तरह से एक नारनौल से चण्डीगढ़ तक की सर्विस भी शुरू की जायेगी।

**चौधरी दल सिंह:** क्या मिनिस्टर महोदय के नोटिस में यह बात है कि लॉग रूट्स पर जो बसें हैं, उनमें से कुछ बसें इतनी कन्डैम हैं कि बीच में ही खड़ी हो जाती हैं ? क्या इस किस्म की बसों को जो लॉग रूट्स पर जाती है, रिप्लेस करने का सरकार कोई इरादा रखती है ?



**कर्नल महा सिंह:** मैंने जैसा कि अभी बताया है, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुरानी बसों को रिप्लेस करें। इस साल के अन्दर हम 80 बसें रिप्लेस कर रहे हैं।

**श्री गिरीश चन्द्र जोशी:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जैसे हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड अपनी ट्रांसफार्मर फ़ैक्ट्री अम्बाला में लगा रहा है, उसी तरह से हरियाणा रोडवेज के लिए भी बाँडी बिल्डिंग की कोई फ़ैक्ट्री लगाने का सरकार कोई इरादा रखती है ?

**कर्नल महा सिंह:** इस वक्त तो कोई ऐसा विचार नहीं है। लेकिन इस सुझाव को एग्जामिन किया जाएगा।

**चौधरी अमीर चन्द कक्कड़:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन डिपुओं में ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है, वहां के आफिसरज को कोई रिवार्ड वगैरा देने की कोई तजवीज है ?

**कर्नल महा सिंह:** वैसे तो हम अपने वर्कज को बानेस देते हैं लेकिन इसके अलावा एक और स्कीम बना रहे हैं जो खास तौर पर छोटे एम्पलाईज के लिए है कि जिसका काम अच्छा हो, उसको इंसेन्टिव के तौर पर कुछ इनाम दिया जाये। वह स्कीम अभी हमने सोची है और उसको एग्जामिन कर रहे हैं।

**श्री के.एन. गुलाटी:** क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह बात दुरूस्त है कि मौजूदा बसों से सब-डिवीजनज को

हिस्सा मिलता है ? अगर यह बात दुरुस्त है तो यह बतायें कि बल्लभगढ़ सब-डिवीजन को किना हिस्सा दिया है ?

**कर्नल महा सिंह:** हमारा एक ऐग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक दिल्ली की बसें चलती हैं। हमारी बसें वहां नहीं चलती। फरीदाबाद की जनता की यह मांग है कि वहां पर हरियाणा रोड़वेज की बसें चलाई जायें क्योंकि पिछले दिनों 'एशिया-72' के दिनों में जब हमने अपनी बसें चलाई, तो उनको पब्लिक ने बहुत अच्छा बताया। जब अगली मीटिंग इस बारे में होगी तो हम दिल्ली वालों से यह मांग करेंगे कि हमारी भी बसें, अगर सारी नहीं तो आधी जरूर, चलनी चाहियें ताकि बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की जनता की मांग पूरी हो जायें।

### **Rural drinking water supply Scheme**

**\*253. Sh. Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the total number of villages covered by Rural Drinking water Supply Scheme in the state upto May, 1968 and upto December, 1972; separately;

(b) the total number of villages which are likely to be covered by the said water supply scheme during the year 1973-74; and

(c) whether the Government intends to give preference to the villages of District Mohindergarh and Hissar where the scarcity of drinking water is too acute?

**Transport Minister (Col. Maha Singh):**

(a) Upto May, 1968

Upto December, 1972

203

562

(b) Approximately 150

(c) Yes.

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** स्पीकर साहब, मेरे इस सवाल के पार्ट बी के जवाब में उन्होंने बताया है 150 गांव 1973-74 में इस स्कीम के तहत कवर होने वाले हैं। वैसे तो कम्पैरेटिवली यह नम्बर बहुत ज्यादा है लेकिन चूंकि वाटर सप्लाई एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है और खास तौर पर उन इलाकों के लिए जहां पर मीठा पानी नहीं है, क्या सरकार इस स्कीम को और बढ़ाने की कृपा करेंगी ?

**कर्मल महा सिंह:** अगर फंडज मिलें तो हम इस स्कीम को और भी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दिक्कत सिर्फ फंडज की है।

**Ch. Mehar Chand:** May I know from the Transport Minister when the rural drinking water supply schemes sanctioned by the Hon. Chief Minister in 1971-72 are likely to be taken in hand and completed?

**कर्नल महा सिंह:** चीफ मिनिस्टर साहब ने जो स्कीमें मन्जूर कर दी है, जैसे-जैसे फंडज मिलते जायेंगे, हम उनको पूरा करते जायेंगे। हमारे पास फंडज की कमी है और इसी वजह से ये स्कीमें पेंडिंग हैं।

**राव अभय सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रिवाड़ी तहसील को, जैसे कि पिछले सेशन में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था, क्योंकि वहां पर खारा पानी है और मीठे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, रूरल ड्रिकिंग वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए प्रायोरिटी दी जायेगी ?

**कर्नल महा सिंह:** इस बारे में जो स्कीमें है, उन पर गौर हो रहा है और वे जल्दी ही फाईनलाईज हो जायेगी। मुख्य मंत्री साहब ने जो कुछ पिछले सेशन में कहा था, उसके मुताबिक ही रिवाड़ी तहसील में तीन स्कीमें सैन्कशन हुई हैं जोकि किसी भी तहसील में सबसे ज्यादा हैं और उन में से दो पर काम हो रहा है। सुलखा के लिए अभी तैयारी की जा रही है और जब फंडज अवेलेबल होंगे तब वह स्कीम शुरू की जायेगी।

**श्री प्रेम सुख दास:** क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि सिरसा कांस्टीचुएँसी में, जहां पर कुल 56 गांव है और उनमें से सिर्फ 12 गांव में पीने का पानी ठीक है और बाकी सब गांवों में पानी खरा है, तवज्जुह दी जायेगी ?

**कर्नल महा सिंह:** हिसार और महेन्द्रगढ़ जिलों की तरह, इस तरफ भी तवज्जुह दी जा रही है इस काम के लिए हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से एक सर्वे पार्टी मिली हुई है और वह सर्वे कर रही है। जैसे कि मैंने अर्ज किया है, ज्यों ही फंडज मिले, हम काम शुरू कर देंगे।

**श्री ओम प्रकाश गर्ग:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कुरुक्षेत्र में यह वाटर सप्लाई स्कीम कहां कहां काम कर रही है ?

**कर्नल महा सिंह:** कुरुक्षेत्र में पानी बहुत मीठा है। पहले पानी वहां दिया जाता है जहां पानी खारा हो, पानी गहरा हो या पानी एक मील से दूर से लाया जाता हो।

**श्री बिहारी लाल वाल्मीकि:** होडल के इलाके में काफी गांव है जहां कि पानी खारा है, क्या वहां पर वाटर सप्लाई की कोई स्कीम है ?

**कर्नल महा सिंह:** जहां पर पानी खारा है, वहां कुछ जगह सर्वे की जा रही है और कुछ जगह की जायेगी और जैसे जैसे फंडज मिलते रहेंगे काम शुरू कर दिया जायेगा।

**चौधरी फूल सिंह कटारिया:** मेरे हल्के में पानी लाने के लिए 72 गांवों का सर्वे किया गया था। वहां इसके लिए तीन स्कीमों हैं, ए., बी. और सी. और उन स्कीमों के अन्दर 32, 21 और 18 गांव हैं लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है।

**कर्नल महा सिंह:** एक स्कीम चालू है और इसी महीने तीन गांवों में पानी शुरू करवा देंगे। नाहड़ का काम काफी दिनों से चालू है और फिर बी. और सी. स्कीमें ले ली जायेंगी।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि करनाल जिले में अमीन गांव की स्कीम काफी दिनों से हैं। यह गांव काफी ऊंचा बसे होने के कारण नीचे से पानी लाने में दिक्कत आती है। बरसात में कीचड़ हो जाती है और उस टाईम बड़ी दिक्कत होती है। मैं जानना चाहता हूं कि उस वाटर सप्लाई स्कीम को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

**कर्नल महा सिंह:** मैं करनाल के भाईयों से कहना चाहूंगा कि करनाल के लोग नहरों से फायदा उठाते हैं। जो जिले जैसे हिसार और महेन्द्रगढ़ है जहां खरा पानी है उनको आगे आने दें।

**चौधरी राम प्रशाद:** मेरी कांस्टीच्यूएँसी जहां पर कि पानी खारा है, कालरा है वहां पर कोई मीठे पानी की स्कीम देने और जो प्राणपुरा की स्कीम है क्या उसको पूरा करने का कोई विचार है ?

**कर्नल महा सिंह:** बावल के लिए जो तीन रिवाड़ी की स्कीमें हैं, उनमें से दो पर सुलखा और प्राणपुरा पर काम शुरू हो गया है लेकिन राव अभय सिंह की फरमाईश पर सुलखा का काम

रोका हुआ है जिससे कि जरथल गुट को उसके साथ मिला दिया जाये ।

### **Licences for Industries**

**\*233. Ch. Ram Parshad:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the total number of applications sponsored to the Government of India for securing Industrial licences during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72 separately;

(b) the total number for Industrial Licences and letters of Intent granted by the Government of India since the 1<sup>st</sup> November, 1966; and

(c) the names of the Important Industries for which licences were issued as referred to in part (b) above?

#### **Industries Minister (Sh. Harpal Singh):**

(a) 681 application have been sponsored to the Government of India as under:-

1969-71	152
---------	-----

1970-71	270
---------	-----

1971-72	259
---------	-----

(b) Licences	121
--------------	-----

Letters of Intent  
1972

312 upto 31<sup>st</sup> December,

(c) List of some of the important industries for which licences and letters of intent have been issued for Haryana is given below:-

1. Paper, Makes Felts.
2. G.L.S. Lamps and Fluorescent tubes.
3. Electric Fans.
4. Caustic soda.
5. Woollen yarn and woollen shoddy.
6. Paper and pulp.
7. Vanaspati (Vegetable Ghee).
8. Room-air Conditioners and Refrigerators.
9. Air and Gas Compressors.
10. Automobile tyres and tubes
11. X-Rays equipment.
12. Record Players
13. Various electric components
14. Tractors
15. Passenger cars
16. Scooters



17. Weighing machines
18. Acetylene gases/oxygen
19. Glass bottles

**चौधरी राम प्रशाद:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लाइसेंस देने में हरिजनों को कोई परैफ्रैन्स दिया जाता है ?

**श्री हरपाल सिंह:** सवाल ही अराइज नहीं होता फिर भी चैक कर लूंगा।

**चौधरी राम लाल वधवा:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनको लाइसेंस दिये गये हैं वे सब हरियाणा की पार्टीज हैं या हरियाणा से बाहर की ?

**श्री अध्यक्ष:** यह तो कोई पूछने की बात नहीं है। सारा देश एक है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** इन्फरमेशन तो आनी ही चाहिए।

**चौधरी राम प्रशाद:** जिला महेन्द्रगढ़ बैकवर्ड जिला करार दिया गया है क्या लाइसेंस देने में वहां कोई रियायत दी जायेगी ?

श्री हरपाल सिंह: कल भी मैंने बताया था कि महेन्द्रगढ़ जिला को बैकवर्ड करार दिया गया है इसलिए हम महेन्द्रगढ़ के लिए एक्सट्रा फ़ैसीलिटीज दे रहे हैं।

### तारांकित प्रश्न संख्या 257

यह प्रश्न पूछा नहीं क्योंकि सम्बन्धित माननयी सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

#### **EXPORT OF INDUSTRIAL PRODUCTS**

**\*262. Rao Abhai Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) the approximate total amount of the industrial products exported from the State during the year 1969-70;

(b) the names of the major and other items of industrial products which were exported during the period referred to in part (a) above; and

(c) the steps which are being taken by the Government for increasing the said export from the State ?

**Minister for Industries (Sh. Harpal Singh):**

(a) Rs. 10.20 Crores

Rs. in crores

(b) Engineering products	6.03
Agricultural and allied products	1.54
Chemical and allied products	1.38
Textiles	1.22
Total	10.20 crores

(c) An intensive drive for export Promotion has been started in the State. The export worthy units have been indentified with the help of Indian Institute for Foreign Trade. They are being encouraged to undertake/ increase the export of their, products for which all types of economic information/facilities are given to them.

**चौधरी शिव राम वर्मा:** क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरिजनों के लिए लाइसेंस देने के लिए कोई कोटा निश्चित किया गया है ?

**श्री हर पाल सिंह:** यह तो सवाल डिफरेंट है। यह जो सवाल था वह एक्सपोर्ट के बारे में था।

**श्री अमर सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक्सपोर्ट का जहां तक सम्बन्ध है जैसे सूरों की एक्सपोर्ट है इस किस्म की एक्सपोर्ट के लिए हरिजनों को लाइसेंस की प्रैफरेंस देने के लिए सरकार तैयार है ?

**श्री हरपाल सिंह:** एक्सपोर्ट के लिए 1969-70 में एक सर्वे किया गया था। सैन्ट्रल गवर्नमेंट का जो फारने ट्रेड इंस्टीच्यूट है उन्होंने 47 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई थी, जिनकी एक्सपोर्ट हो सकती है। उनके लिए 103 यूनिट वर्क कर रहे हैं। उनकी एक लिस्ट भी बनी हुई है। उनकी एक रिपोर्ट भी छपी है। अगर आनरेबल मेंबर उस रिपोर्ट को देखना चाहें तो वह मिल जायेंगी।

**चौधरी पीर चन्द:** अगर हरिजनों को लाइसेंस देने में प्रैफैन्स देने के लिए सरकार राजी नहीं है तो कम से कम सब हरिजनों को एक्सपोर्ट कर दिया जाये जिससे कि यहां कोई हरिजन न रहे। (हंसी)

### **तारांकित प्रश्न संख्या 282**

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 282 श्री फूल चन्द मुलाना का है जो कि 26 तारीख तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। (प्रश्नोत्तर काल समाप्त)

**नियम 45 के अधीन पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित  
उत्तर**

**\*286. Sh. Hari Singh Nalwa:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) the total amount spent for the development of Haryana Agricultural University in the State from 1<sup>st</sup> April, 1968 to 31<sup>st</sup> March, 1972;

(b) the main items on which the said amount has been spent; and

(c) whether the Government further intends to develop the Haryana Agricultural University, if so in what respect?

**कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल):**

(ए) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 2-2-70 से अस्तित्व में आया है। 2-2-70 से 31-3-72 तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विकास पर कुल 462.81 लाख रुपये खर्च हुये। इसके अतिरिक्त इसी मध्य 281.21 लाख रुपये अनुरक्षण पर खर्च हुये है।

(बी) मुख्य आइटम जिन पर यह राशि खर्च हुई है, निम्न है:-

1. भवन निर्माण
2. अध्ययन
3. अनुसन्धान

4. विस्तार शिक्षा

5. फार्म

(सी) हां। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को उसके मास्टर प्लान, जो पहले से ही तैयार है, अनुसार एक बहुमुखी कृषि विश्वविद्यालय बनाने का विचार है।

#### **Bus Stand at Dadri Town**

**\*311. Sh. Ganpat Rai:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand at Dadri Town;

(b) if so, the site where it is proposed to be constructed;

(c) the time by which it is likely to be completed?

**परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह):**

(क) हां।

(ख) स्थान के चयन के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

(ग) इस बारे में कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

### **Persons Died in Police Custody**

**\*182. Ch. Dal Singh:** Will the Minister for Home be pleased to state:-

(a) the total number of persons with their addresses who died while in police custody during the year 1970-71 and 1971-72 in the state;

(b) the number out of the cases referred to in part (a) above for which the Police Officers were held responsible;

(c) whether any cases were registered against the Police Officers referred to in part (b) above in the years 1970-71 and 1971-72,

(d) the number of officers referred to in part (c) above together with their addresses who were punished in the year 1970-71 and 1971-72?

**गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल):**

(क) 1970-71 और 1971-72 में क्रमशः एक और तीन मनुष्यों की मृत्यु पुलिस की हिरासत में हुई। उनके पते नीचे दिये जाते हैं।

1970-71

1. सुभाष चन्द्र, पुत्र मूलशंकर, निवासी माडल टाऊन पानीपात, जिला करनाल।

1971-72

1. राजू, पुत्र रामचन्द्र हरिजन, निवासी कोट पुरा, थाना बरोदा, जिला रोहतक।

2. कीडू, पुत्र लेख राम नायक, निवासी बधंरधरा, थाना सदन, हिसार।

3. हेत राम पुत्र किशाना बावरिया, निवासी दहोवी, थाना कलायत, जिला जींद।

(ख) उपर्युक्त चारों मामलों में किसी भी पुलिस आफिसर को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### **Holiday in Government Schools**

**\*187. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for education be pleased to state:-



(a) the total number of days for which Government Schools remain closed during a year including Sundays and other holidays; and

(b) whether the Government proposes to reduce the number of close days/holidays in the Government Schools to improve the education?

**शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक):**

(ए) 118

(बी) नहीं।

**Transfer to villages from district Hissar to District Bhiwani**

**\*199. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the inhabitants of 17 villages, including villages Hanta, Talwandi Ruka, Talwandi Badshahpur, Sharwa, submitted a representation to the Government for keeping them in Hissar Tahsil instead of transferring them to Bhiwani District; and

(b) if so, the action so far taken by the Government on the said representation?

**राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा):**

(ए) जी नहीं। 17 गांवों में से केवल 7 निम्नलिखित ग्रामों के निवासियों से ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं:-

1. चिरौद
2. डाहा
3. भोज राज
4. चांद नौद
5. हरीटा
6. बुरे
7. रावत खेड़ा

(बी) प्राप्त आवेदन पत्र सरकार के विचारधीन है।

### **Amenities in Haryana Roadways Depots**

**\*200. Ch. Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Transport be pleased to state whether any amenities of Rest rooms, latrines, drinking water and Restaurants have been provided in the Haryana Roadways Depots opened during the year 1972?

**Transport Minister (Col. Maha Singh):** During the year 1972, only one depot was opened at Rewari where all amenities of rest rooms, latrines, drinking water and Restaurants exist in the Bus Stand Building adjacent to the depot.

## **Election of the Co-operative Societies**

**\*214. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the district-wise names of Co-operative Societies in the State to which elections were held 3 years ago or earlier together with the time which Election thereto are likely to be held:-

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): सूचना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ नहीं होगा।

## **Bus Stand etc.**

**\*250. Ch. Brij Lal:** Will the Minister for Transport be pleased to state:-

(a) the total number of Bus Stands, Bus Queue Shelters and pick up shelters in the State on 1st May, 1968 and 31st December, 1972, separately;

(b) the total number of Bus Stands, Bus Queue Shelters and Pick up Shelters which are likely to be constructed in the year 1972-73; and

(c) whether the Government intends to make some arrangements for drinking water at Bus Queue Shelters?

## **Transport Minister (Col. Maha Singh):**

		Bus Stands	Bus Queue	Pick-up

			Shelters	Shelters
(a)	On 1st May, 1968	4	6	2
	On 31st December, 1972	12	17	15
(b)	To be constructed during the year 1972-73		1	2
(c)	Drinking water facilities exist at all Shelters except at Raipur Rani where such arrangement would be made shortly.			

### **Metalled Roads**

**\*254. Sh. Jagjit Singh Tikka:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

(a) the total mileage of metalled roads in the State upto May 1968 and upto December, 1972, separately;

(b) the total number of villages covered by the metalled roads upto December, 1972; and

(c) the total mileage of metalled roads which are likely to be constructed togetherwith the villages which are to be covered by the said metalled roads during the year 1973-74 ?

**राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा):**

अपेक्षित सूचना निम्न दी जाती है:—

(ए) (1) राज्य में मई, 1968 तक बनी पक्की 5650 किलोमीटर सड़कों की कुल लम्बाई

(2) राज्य में दिसम्बर, 1972 तक बनी 13065

किलोमीटर

पक्की सड़कों की लम्बाई

(बी) दिसम्बर, 1972 तक पक्की सड़कों से मिलाये

3873

गये ग्रामों की कुल संख्या

(सी) वर्ष 1973.74 के दौरान पक्की सड़कों की कुल लम्बाई, जो कि बनाई जानी है तथा इस द्वारा मिलाये जाने वाले ग्रामों की कुल संख्या :—

(1) पक्की की जाने वाली लम्बाई

(2) उक्त लम्बाई से मिलाये जाने वाले ग्रामों की संख्या

इस समय कुछ भी बताना संभव नहीं है क्योंकि योजना आयोग ने इस वर्ष सड़कों के निर्माण के लिये कम महत्ता दी है।

**चौधरी चांद राम:** स्पीकर साहब, मैंने आपको जबानी कहा था कि मेरी सीट और पीछे कर दो तो अच्छा रहे। .....(हंसी).....

**Chief Minister( Chaudhri Bansi Lal):** You are in a good company....(Laughter)

**चौधरी चांद राम:** मैं इस कम्पनी से घबरा जाता हूँ .....(हंसी).....जनाब इस बात का फैसला कब तक हो जायेगा (व्यवधान) ।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** स्पीकर साहब, आपने चौधरी हरद्वारी लाल, चौधरी चांद राम और मुझ को एक कूण में कर दिया है।.....(हंसी).....

**श्री औमप्रकाश गर्ग:** स्पीकर साहब, मेरी एक गुजारिश है कि इनकी सीट बदलावें या न बदलावें पर इनके कपड़े चौधरी हरद्वारी लाल जैसे बदलवा दें .....(हंसी)..... ।

### **कार्य मन्त्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन**

**श्री अध्यक्ष:** मैं विभिन्न कार्य के सम्बन्ध में कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करता हूँ।

कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने सिफारिश की कि 7,8,9,12 तथा 13 तार्च, 1973 को निम्नानुसार कार्य किया जाये:-

7मार्च, 1973

1 प्रश्न समय ।

2 कार्य मन्त्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन ।

3 सदन की मेज पर पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र

(क) हरियाणा पशु मेला निमावली, 1970

(ख) हरियाणा आकस्मिकता निधि (प्रथम संशोधन)  
नियमावली, 1972 ।

4 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ करना ।

8 मार्च 1973

1 प्रश्न समय ।

2 अनुपूरक प्राक्कलन (द्वितीय किश्त) 1972.73 पेश  
करना ।

3 अनुपूरक प्राक्कलन (द्वितीय किश्त) 1972.73 पर  
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन पेश करना ।

4 गैर सरकारी कार्य ।

9 मार्च, 1973

1 प्रश्न समय ।

2 वर्ष 1973-74 का बजट पेश करना ।

12 मार्च, 1973

1 प्रश्न समय।

2 अनुपूरक प्राक्कलन (द्वितीय किश्त) 1972-73 पर चर्चा तथा मतदान।

13 मार्च, 1973 (दो बैठकें)

प्रथम बैठक 9.30 बजे प्रातः

1. प्रश्न समय।

अनुपूरक प्राक्कलन(द्वितीय किश्त) 1972-73 पर विनियोग विधेयक।

द्वितीय बैठक 2.00 बजे मध्याह्न के पश्चात्

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद-प्रस्ताव पर मतदान।

**चौधरी रिजक राम:** स्पीकर साहब, 13 तारीख को आपने जो प्रोग्राम के मुताल्लिक फरमाया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर दूसरी सिंटिंग में (2 बजे से साढ़े छः बजे तक) बहस होगी अगर आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पहली सिंटिंग में बहस रख लें तो ठीक रहता।



**श्री अध्यक्ष:** चौधरी साहब, इसी सिलसिले में मैंने आपसे टेलीफोन पर भी बात करने का प्रयत्न किया था मगर आप मिल न पाये। इसी तरह से जैसे मैंने रखा है गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन करने के लिये ज्यादा समय मिल सकेगा। इसीलिये मैंने यही मुनासिब समझा क्योंकि 2 बजे से साढ़े छः बजे तक हमें पूरे साढ़े चार घंटे बहस के लिये मिल जायेंगे।

**मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल):** स्पीकर साहब, हमारी तरफ से तो खुली छुट्टी है। जैसे चौधरी रिजक राम जी चाहें कर ले। हमें कोई एतराज नहीं है।

**चौधरी हरद्वारी लाल:** स्पीकर साहब, मैं गवर्नर एड्रैस पर बोल संकूगा या नहीं?

**श्री अध्यक्ष:** हां, बोल सकेंगे।

**Home Minister (Shri K.L. Poswal):** Sir, I beg to move -

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

**श्री अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्न यह है -

कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

### पटल पर पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र

**Development Minister (Shri Shyam Chand):** Sir, I beg to relay on the Table a copy of the notification No. G.S.R. 131/H.A.30/70/S.22/70, dated the 7<sup>th</sup> December 1970 regarding the Haryana Cattle Fairs Rules, 1970, as required under section 22(3) of the Haryana Cattle Fairs Act, 1970.

**Home Minister (Shri K.L. Poswal):** Sir, I beg to relay on the Table a copy of the notification No. G.S.R.-158/T.A.2/67/S.6/72, dated the 23<sup>rd</sup> June, 1972, regarding the Haryana Contingency Fund (First Amendment) Rules 1972, as required under Section 6(2) of the Haryana Contingency Fund Act, 1966.

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

(इस समय चौधरी दल सिंह बोलने के लिए खड़े हुये)

**श्री अध्यक्ष:** चौधरी साहब, आप 33 मिनट कल बोल चुके हैं, अब आप 10 मिनट और बोल सकते हैं।

**चौधरी दल सिंह(जींद):** स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है कि 10 मिनट का टाईम तो कुछ नहीं है। मेरी आप से प्रार्थना है कि मुझे पुरा टाईम बोलने के लिये दिया जावे।

स्पीकर साहब, कल मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुये एक पैम्फ्लैट का जिकर कर रहा था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से शायी किया गया है। मैं उस तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उस पैम्फ्लैट के पेज 10 पर सरकार की तरफ से लिखा गया है।

“The local body schools were provincialised with effect from 1<sup>st</sup> October, 1957 in the composite State of Punjab. The provincialised employees who were over 30 years of age on 1<sup>st</sup> October, 1957 were allowed to continue under the contributory Provident Fund Scheme under Government and those employees above 30 years of age on 1<sup>st</sup> October, 1957, who were deprived of the pensionary benefits, have been representing that discrimination in the matter of grant of pensionary benefits to the provincialised employees on the basis of age limit should be removed, and they should also be allowed pensionary benefits. No decision on this demand could be taken in the composite Punjab State. This matter is already under consideration of the Haryana Government. Punjab Government has, however, given this benefit to its employees.”

स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार कहती है कि अध्यापकों की जो मांगे हैं, वे जायज नहीं हैं और दूसरी तरफ अपने ही द्वारा छापे गये पैम्फ्लैट में यह स्वीकार करती है कि लोकल बाडीज स्कूलज को 1 अक्टूबर, 1957 से गवर्नमेंट के दायरे में लिया गया था। उस वक्त यह फैसला किया गया था कि जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 1957 को 30 साल से ऊपर थी, उन्हें

कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फन्ड के तहत ही रहने दिया जाये व जिनकी उम्र 30 साल के नीचे थी उन्हें पेंशन बेनेफिट आप्ट करने की आज्ञा दी गई थी पर 30 साल की उम्र से ऊपर वालो को पेंशन बेनिफिट से वंचित रखा गया। उन्होने यह डिमांड की कि जों हमें उम्र ज्यादा होने के कारण इस पेंशन बैनिफिट से वंचित रखा जा रहा है, यह नहीं होना चाहिये। पर पंजाब सरकार ने तो अपने एम्पलाईज को पेंशन बैनिफिट दे दिया पर हरियाणा की सरकार यह कह रही है कि यह मामला अभी जेरे-गौर है। समझ मे नही आ रहा कि आज 7 साल हो चले है, अभी तक यही कहा जा रहा है कि अभी मामला अन्डर कंसीड्रेशन है कि हम पेंशन का बैनिफिट देंगे। इसके बाद तो बहुत से टीचर रिटायर भी हो चुके है। तो इस किस्म की बात पहले खुद कहें और फिर बाद में पब्लिक में इन्कार करें, यह कोई यमझदारी की बात नहीं है। टीचर्ज की मांग न्यायोचित है और बेस्ड करती है फौक्ट्स पर, रूल्ज पर। इसलिये जो हड़ताल हुई है, उसका जिक करते हुये सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पैम्फलैट के पेज5 पर इन्होंने यह माना है कि –

“2. Sanctioning of D.A. to the teachers like other employees:-

(a) Grades are revised in respect of school teachers, Police personnel, college teachers and Ministerial staff of Haryana State after 1<sup>st</sup> November, 1966, during Governor's regime. A cut was imposed by the authorities whicle revising grades in respect of the school teachers and

police. On assuming office in 1968, the Bansi Lal Government hastened to restore, D.A. cut in respect of police personnel but our long standing demand was cut, ignored and has never been considered thereafter. No cut was imposed in respect of college teachers and Ministerial staff.”

1 नवम्बर, 1966 के बाद सरकार ने सभी कैटेगरीज के ग्रेडज रिवाइज किये, जिस में स्कूल, कालेज टीचर्ज व मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और पुलिस सभी शामिल है। सरकार ने कट लगाई और गवर्नमेंट के सभी एम्पलाइज उस में शामिल थे। सभी का कट रैस्टोर कर दिया पर टीचर्ज का रैस्टोर क्यों नहीं किया? यह एक अजीब सी कहानी है कि एक के साथ न्याय किया जाये और एक को देने से इन्कार किया जाये और दुसरी तरफ पैम्फलैट के पेज 7 पर लिखा है कि :

“This policy is quite contrary to the recommendations of the Education Commission headed by Dr. Kothari which clearly states that adjustment of the teachers should be made near their home station.”

अब उनकी जो ट्रांसफर पालिसी है सरकार को वह भी खटकी । डाक्टर कोठारी जो महा विद्वान है इस सिलसिले में उनकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने अमल किया है। लेकिन यहां यह हालत है कि जो ला पेड सरकारी कर्मचारी है उनको उनके घर से दूर ट्रांसफर किया जाता है जबकि रिपोर्ट में यह है कि उनकी उनके घर से नजदीक से नजदीक रखा पाये ताकि उनके खर्च में बचाव हो सके। हमारी सरकार ने टीचरों को आर्डर दिया

है कि घर से 20 मील दूर जाओ। टीचरों को जहां भेजा गया है वहां रहने के लिये मकान नहीं है जिसके कारण वे बड़े परेशान होते हैं। उनको साइकिलों पर जाना पड़ता है। 20 मील साइकिल पर जाने के लिये कम से कम अढ़ाई घंटे चाहियें और आधा घंटा तैयार होने के लिये चाहिये। इसी प्रकार तीन घंटे वापिस आने के लिए चाहिये। अगर कोई कहें कि यह पालिसी ठीक है तो यह बात मेरी समझ से बाहर है। हमारे शिक्षा मंत्री भी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस पालिसी ने हरियाणा की एनूकेशन का भट्ठा बिठा दिया है। डाक्टर कोठारी जिनके फैसले पर आप सब पाबन्द हैं, सारे भारत की सरकारें पाबन्द हैं लेकिन शायद हरियाणा सरकार पाबन्द नहीं है। यह वही सरकार है जिसने टीचरों की डिमांड को न मानकर पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया। मैं समझता हूँ टीचरों की यह डिमांड जायज है। मेरे पास यह पैम्फलेट है जिसके पेज 10 पर पेंशनरी बैनिफिट्स टू लोकल बाडीज एम्पलाइज के बारे में लिखा है। ये भी यही कहते हैं कि उनको पेंशन का हक मिलना चाहिये और सरकार भी कहती है कि हमारे जेरे गौर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सात साल से यह जेरे गौर है अगर इतना टाईम जेरे गौर में ही लगता रहा तो समझो भट्ठा बैठ गया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उससे जो गलती हुई है उसको ठंडे दिल से सोचें और अपनी गलती को मानें। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हमारी जो प्रधान मंत्री है, वे देश की सर्वे-सर्वा है। टीचर्ज के लिये जो उन्होंने कहा वह मैं पढ़ देना चाहता हूँ। टीचर्ज के सारे भारत वर्ष में सरकारी तौर पर

मनाया जाता है। स्पीकर साहब, राष्ट्रपति जी का औहदा देश में सबसे बड़ा है पहले मैं वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा।

दूसरे पैम्फलेट के पेज 13 पर लिखा है –

“On the other hand, honourable President of India, Dr. V.V. Giri, has expressed his views on the teachers day (5<sup>th</sup> September, 1972) as follows:-

It is incumbent on society to ensure that the teacher is given proper status and emoluments commensurate with the nation-building task he performs.”

यह हमारे राष्ट्रपति कहते हैं इससे ज्यादा बड़ी और कोन सी हस्ती इस देश के अन्दर है जो टीचर्स की भलाई के लिए कह सकती है। इसी पेज पर हमारी प्रधान मन्त्री जी कहती हैं—

“ The Honourable Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi made the following remarks on 5<sup>th</sup> September, 1972:-

The Work of teachers is of the utmost importance to the development of a nation. Hence society must give them an honourable status and provide conditions in which they can give of thier best.”

उन्होंने फरमाया है कि टीचर्स की ज्यादा से ज्यादा रिस्पैक्ट की जाये, इज्जत की जाये। लेकिन स्पीकर साहब बड़े अफसोस की बात है कि यहां टीचर्स को कितना मान दिया गया?

यह सब को भली प्रकार मालूम है कि उनके ऊपर झूठे मुकदमें बनाकर उनको परेशान किया गया है। टीचर्ज की रिस्पैक्ट के लिये हमारी प्रधान मन्त्री ऐलान करती हैं, देश के राष्ट्रपति ऐलान करते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार? हरियाणा सरकार या तो यह कहे कि हम राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री से ऊपर हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां भी कांग्रेस की सरकार हैट और सैंटर में भी कांग्रेस की सरकार है लेकिन फिर भी अगर यह सरकार उनकी मांगों पर गौर न करे तो समझ से बाहर की बात है।

**श्री अध्यक्ष:** आपका समय 5 मिनट और है

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, मैंने अभी कुछ नहीं कहा है मुझे और बोलने दीजिये।

**श्री अध्यक्ष:** और लोगों ने भी बोलना है।

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, आप टाइम बढ़ा दे।

**श्री अध्यक्ष:** आपको बजट पर भी मौका मिलेगा उस समय बोल लेना।

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, बजट पर मैं नहीं बोलूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** आपको बजट पर बोलने के लिये जरूर टाई दिया जायेगा।



**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, इन पैम्फलैटों की बातों के अलावा मैं कुछ और बातें बताना भी जरूरी समझता हूँ। यहां पर जो जे0बी0टी0 टीचर्स का नया एप्वांयटमेंट होता है उनका स्केल 125-5-250-10-300 होता है इस पर 98 रुपये डी0ए0 होता है और 18.50 कट इस प्रकार 79.50 रुपये एक्चुअल उसको मिलता है। लेकिन पुराना जो जे0बी0टी0 टीचर है उसका ग्रेड 60-4-80-5-100 है डी0ए0 98 रुपये और कट 18.50 रुपये। इस प्रकार एक्चुअल डी0ए0 79.50 रुपये। एक ग्रेड तो 125 रुपये से शुरू होता है और दूसरे का 60 रुपये से शुरू होता है लेकिन कट वही 18.50 लगाई जाती है। चाहिये तो यह कि जिसकी तनख्वाह ज्यादा हो उस पर ज्यादा कट लगे और जिसकी कम उस पर कम कट लगे। इसके अलावा जे0बी0टी0 टीचर जिसकी तनख्वाह 1-12-67 को 110 रुपये थी उसके ऊपर 35 रुपये की कट लगती है और 1-12-67 के बाद जो जे0बी0टी0 टीचर सिलैक्शन ग्रेड में आया उसके ऊपर 18.50 कट लगती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारे डिस्पेरेटिज क्यों हैं? मेरे ख्याल में सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसी तरह बी0ए0, बी0एड0 और बी0टी0 का 220 रुपये से ग्रेड शुरू होता है जिसके साथ 146 डी0ए0 है और 41 रुपये कट लगने के बाद 105 रुपये रह जाता है। जो 1-12-67 को सिलैक्शन ग्रेड में था उसकी तो 10 रुपये कट लगाई जाती है और जो 1-12-67 के बाद सिलैक्शन ग्रेड में आया उस पर 41 रुपये कट लगाई जाती है। यह बात गौर करने की है कि जिस को ज्यादा पैसा मिलता है

उसकी कट तो 10 रूपये है और जिसको कम पैसा मिलता है उसकी कट 41 रूपये है इसी तरह से हमारे जो शास्त्री है उनका ग्रेड 220 रूपये से शुरू होता है और जो पुराने जे०बी०टी० 110 रूपये से शुरू होने वाले ग्रेड में थे ओर अब उन्होंने बी०ए०, बी०एड० कर ली है उनका ग्रेड भी 220 से शुरू होता है इन दोनों के डी०ए० पर भी 18.50 रूपये कट की है। क्या कोई आदमी इस बात को तसलीम करने के लिये तैयार है कि टीचर्ज के सागि यह अन्याय नहीं है। इसी तरह से शास्त्री, प्रभाकर, पी०टी०आई० और क्लासीकल वर्नेकुलर टीचर्ज है इस कैटेगरी में शास्त्री का ग्रेड तो 220 रूपये से शुरू होता है बाकी सब का 125-5-250 से होता है। इसी तरह क्लास 3 के जो लैक्चरर है उनका ग्रेड 250-25-550-30-600 का है और बी०एड० और बी०टी० का 220-8-300-10-400-20-500 है इन दोनों में एक को तो 25 रूपये इंकरीमेंट मिलता है और दूसरे को 8 रूपये लेकिन कट दोनों की 50-50 रूपये होती है जबकि दोनों के इंकरीमेंट में 17 रूपये का अन्तर है।

**एक आवाज:** यह कोठारी कमीशन की ही रिपोर्ट है।

**चौधरी दल सिंह:** मैं एग्री करता हूँ कि आप कोठारी कमीशन की रिपोर्ट माने इसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कमीशन तो कहता है कि पांच साल के बाद ग्रेड रिवाइज करो।

स्पीकर साहब, पंजाब और हिमाचल में 1-12-1966 से ग्रेड दिये गये जबकि हरियाणा में एक साल लेट यानि 1-12-67 से दिये गये। यह भी एक किस्म के टीचरों के साथ अन्याय है। एक मेंट्रीकुलेट क्लर्क जब भरती होता है उसे 208 रूपये मिलते हैं लेकिन एक जे०बी०टी० टीचर जो दो साल की ट्रेनिंग करता है उसे 204.50 मिलते हैं। यह बिल्कुल गैर इंसाफी है।

फिर नई बात यह है कि अगर एक मेंट्रीकुलेट बी०ए० पास करता है तो उस को दो एंकरमेंटस दी जाती है लेकिन उन के मुकाबले में अगर कोई जे०बी०टी०, बी०ए०, बी०एड० पास कर ले तो उस को कोई इंकरमेंट नहीं दी जाती। मैं समझता हूं कि यह सरकार की गलत नीति है और भेदभाव की पालिसी है जिस को ठी करना चाहिये। गवर्नमेंट चाहे जिनते मर्जी पैम्फ्लैट छपवाले लेकिन लोग सच्चाई को समझते हैं ओर उनको गुमराह नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहब इन्होंने कहा है कि जो तमाम डी०ढ० था वह तनख्वाह में मिला दिया है लेकिन तब तनख्वाह का बिल तैयार होता है तो उसमें दोबारा डिडक्शन होती है। इससे साफ जाहिर है कि आप का कहना कुछ है ओर करना कुछ है। यह टीचर्ज के साथ बड़ी भारी अन्याय है। टीचर्ज की स्ट्राइक को फेल करने के लिये सरकार की तरफ से जो हरबे इस्तेमाल किये गये हैं उनका जिक्र मैंने कल भी किया था। स्पीकर साहब हमारे सामने ऐसी-ऐसी बातें आई हैं जिन के बारे में आज तक हमने न कभी सुना है और नहीं देखा है। अप्वायंटमेंट का तरीका यह होता

है कि अगर किसी की पक्की अप्वांटमेंट करनी हो तो उस को सबार्डिनेट सर्विस सलैक्शन बोर्ड करता है और अगर कोई कच्चा टीचर लगाना हो तो उसे डी0ई0ओ0 लगाता है। इसके अलावा हम ने कभी नहीं सुना कि कोई दूसरा कर्मचारी उनको लगा सके। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि जब स्ट्राइक हुई तो इनका एक कानूनगी गांव में जाता है और कहता है कि गांव में उन आदमियों के नामों की लिस्ट बनाकर दो जो मैट्रिकुलेट है। यहां पर एक थर्ड डिविजन मैट्रिकुलेट था और एक अन्डर मैट्रिक था। अन्डर मैट्रिक उस का रिश्तेदार था इसलिये उस कानूनगी ने उसको कहा कि मैं तुम को टीचर अप्वायट करता हूं।

**Education Minister (Shri Maru Singh Malik):** It is wrong.

**Chaudhri Dal Singh:** It is a fact. I tell you it is a fact, I can swear this on oath. I am telling the truth. You can say anything. You may say whole world is wrong. आप चाहें जो मर्जी कहें लेकिन मैं कहता हूं कि आप के कानूनगो ने उस गांव में अन्डर मैट्रिक को लगाया। हमने आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जिस का कानूनगो गांव में जाकर टीचर को लगाये। फिर इन के एस0डी0ओ0 साहब गांव में जाते है। गांवो में आप जानते है कि पार्टीबाजी तो होती ही है। कोई खिलाफ कहने वाला होता है और दूसरा हक में कहने वाला होता है। मास्टर वहां पर मौजूद नहीं था उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया। फिर वह कहते है कि जो टीचर अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होगा

उसको पुलिस के जरिये जबरदस्ती स्कूल में हाजिर किया जायेगा। मैं समझता हूँ कि डैमोकेसी में यह बड़ी भारी ज्यादाती है जिसको कि बरदाश्त नहीं किया जा सकता। टीचर्ज के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वे हमारे देश का गौरव है, वे नेशन को बनाने वाले हैं, अगर उनका अपमान यिका गया तो हरियाणा प्रांत तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप को उन के प्रति कोई गुस्सा है तो हम माफी मांगने के लिये तैयार हैं और टीचर भी माफी मांगने के लिये तैयार हैं लेकिनउनकी जो जायज मांगे हैं उनको जरूर मान लेना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष:** आप को एक घण्टा हो गया है णैधरी साहब अब आप वाईड—अप करें।

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, मुझे और टाईम मिलना चाहिये, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ।

**श्री अध्यक्ष:** पांच मिनट आप और बोल लें।

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, मुझे आप दस मिनट ओर दे दे।

**श्री अध्यक्ष:** आप जन्दी वाईड—अप करें।

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, जब भी कोई मौका आता है तो सरकार यह कहती है कि अगर टीचर्ज की मांग को मान लें तो उस पर खर्च बढ़ा होगा। इसके लिये मैं उनको सुझाव

देता हूँ कि वे मिनिस्टर साहब जो दौर करते हैं, अगर उनको वे कम करें और टी0ड0, डी0ए0 वगैरह लेना बन्द कर दें तो बहुत सा खर्चा पूरा हो सकता है। 28 फरवरी को जो पुल का उद्घाटन समारोह हुआ था, उस अवसर पर फूलों से वर्षा करने के लिये हवाई जहाज घुमाया गया जिसका कि कॅश हुआ और उस हाइसे में एक चीफ इंजीनियर मारा गया और उस जहाज का पायलैट अभी अस्पताल में पड़ा हुआ है। इतनी फिजुल-खर्ची की जा रही है। पुल के पास एक लेक बना दी है जिस पर आठ लाख रूपया खर्च किया गया है।

**कृषि मंत्री (चौधरी भजनलाल):** आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह जी ने यह बात कही है कि पुल के उद्घाटन के समय फूलों की वर्षा करने के लिए हवाई जहाज घुमाया गया जिसका कि कॅश हुआ। यह बात गलत है क्योंकि पुल का उद्घाटन तो 5.15 पर होना था लेकिन जहाज का एक्सीडैन्ट चार बजे हुआ।

**Chaudhri Dal Singh:** I am telling a fact. The Hon'ble Minister telling another fact. (*Interruption*) May be, you were making preparation.

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हरियाणा की सरकार ने जगह-जगह पर गलत कामों पर पैसा खर्च किया है और अपने ऐशोआराम के लिये लाखों रूपये खर्च कर दिये लेकिन दूसरी तरफ गरीब लोग रोटी के लिये तरस रहे

है। इनको अपने लिये ठंडे कमरों की जरूरत है। जिस स्टेट में लोगों की ऐसी हालत हो वहां पर फिजूलखर्ची करना मुनासिब बात नहीं ।

**चौधरी मेहर चन्द:** स्पीकर साहब, मुझे पता नहीं कि जो कुछ मैं कहने लगा हूं वह प्वाइंट आफ आर्डर बनता है या नहीं। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या आप सारा टाई इनको एक्सटेंशन में ही देते रहेंगे, हमारा नम्बर भी तो आना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष:** आप का नम्बर भी आयेगा।

**चौधरी दल सिंह:** एक सवाल में गवर्नमेंट ने खुद यह माना है कि दस लाख रूपया खर्च किया है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसी फजूलखर्ची बन्द कर दी जायें तो हरियाणा के टीचर्स की जायज मांगों को पूरा किया जा सकता है। मैं हिमाचल की मिसाल देना चाहता हूं। हमारी सरकार यह कहती है कि हमारी पर-कैपिटल इन्कम सारे हिन्दोस्तानमें दूसरे नम्बर पर है। हम भी इनकी इस बात को सच मान लेते हैं। जब इतनी खुशहाली है तो फिर क्या वजह है कि टीचर्स की जो जायज मांगे हैं वह न मानी जायें। हिमाचल में हम से कम इन्कम है उन्होंने हमारी स्टेट से ज्यादा ग्रेड दिये हैं। मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहब को मनाना चाहिये कि वह गरीब टीचर्स के साथ इस तरह का स्टिक रवैया अख्तियार न करें। उन की जायज

डिमांडें चीफ मिनिस्टर साहब को माननी चाहिये। अगर आप हमारी बात नहीं माना चाहते तो आप राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री की ही बात मान लें। मैं समझता हूँ हम सब की ज्वायंट रिस्पोंसिबिल्टी है लेकिन यहां पर अजीब सी बात हो रही है। स्पीकर साहब, यहां पर ऐसा खेल हो रहा है जैसे गांव में कोई लड़की.....के साथ खेलती हो, कभी उसका मुंह से परदा उठाकर लड़की बना देती है, कभी उसके मुंह पर पर्दा डालकर औरत बना देती है, कभी उस को सुला देती है और कभी बैठा देती है। तो यह सारे वुज़रा भी उस.....की तरह है, चीफ मिनिस्टर साहब जैसे उनको इधर उधर बैठाना चाहते हैं बैठा देते हैं और.....जैसा ही खेल कर रहे हैं।

**चौधरी भजनलाल:** स्पीकर साहब, यह जो.....का लफ़्ज इस्तेमा किया गया है इस ऐक्सपंज करवा दिया जाये क्योंकि यह अन-पार्लियामेंटरी है।

**श्री अध्यक्ष:** यह जो .....के शब्द है इनको ऐक्सपंज कर दिया जाये।

**चौधरी दल सिंह:** एक बात मैं आखिर में और करना चाहता हूँ, आप को पता है कि टीचर्ज़ की मांगो को मनवाने के लिये अध्यापक संघ के जो लीडर्ज है, जो कि महान व्यक्ति है उन्होंने अनिश्चितकाल के लिये भूख हड़ताल रखी हुई हैं। मैं हाउस के फ्लोर पर इस बात की वार्निंग देता हूँ कि अगर कोई



गलत घटना हो गई तो हरियाणा सरकार के माथे पर जो कलंक का धब्बा लगेगा उस को गंगा और जमुना के पानी से भी नहीं धोया जा सकेगा। मैं अर्ज करता हूँ कि वे तशद्द पर नहीं है (घंटी) स्पीकर साहब आप मुझे सिर्फ दो मिनट और दें (घंटी) अच्छा तो स्पीकर साहब मैं इन अलफाज के साथ राज्यपाल के इस अभिभाषण का विरोध करता हूँ। स्पीकर साहब मैं एक बात ओर अर्ज करता हूँ कि मैंने जेल से चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी। मैं उस लैटर की कापी यहां हाउस में रखना चाहता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी।

**चौधरी राम लाल वधवा(करनाल):** स्पीकर साहब, आज गर्वनर साहब के एड्रैस पर डिस्कशन हो रही है ओर में इस पर बोलते हुये यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले सैशन ओर इस सैशन के दौरान में एक महत्वपूर्ण बात हुई थी और उसका इस मौके पर जिक्र करना जरूरी सूझता हूँ क्योंकि हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते है ओर यह प्रजातन्त्र तभी अच्छे ढंग से चल सकता है जब उसके अन्दर एक स्ट्रांग अपोजीशन हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक साथी ने अपोजीशन में बिकरिंग पैदा करने कि लिये जो रोल अदा किया वह हरियाणा के इतिहास में अच्छा नहीं समझा जायेगा। पता नहीं उन्होंने किस गर्ज को लेकर किस तरीके से पार्ट प्ले किया लेकिन उनके बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि उन्होंने इस रिवायत पर अमल किया कि 'खुद तो डूबेंगे सनम तुझ को भी ले डूबेंगे'। पता नहीं वह

बनना क्या चाहते थे? क्षमा करें अगर मैं इस बारे में एक मिसाल पेश करूं जो मुझे याद आ गई हैं। हरियाणा के अन्दर ही वह आदमी पैदा हुआ था और हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र के अन्दर उसका मकबरा भी बना हुआ है जिसकी यह मिसाल है। उसका नाम था शेख चिल्ली। कहते हैं कि एक बार वह अंडों का टोकरा सिर पर उठाये जा रहा था। वह सोचता जा रहा था कि अंडों से बच्चे पैदा होंगे वह बड़े होंगे तो उनको बेच कर गाय खरीदूंगा। गाये बच्चे देगी तो बड़ा होने पर उनको बेच कर और धंधा करूंगा ओर जाते जाते उसने कई कुछ सोच लिया कि अमीर हो जाऊंगा और शादी करूंगा और बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे। परिवार बढ़ेगा। जब वह मुझ से कुछ मांगने आयेगे तो मुझे गौरव होगा ऐसा सोचते सोचते गौरव से सिर हिला दिया और सिद हिलानेसे अंडो का टोकरा नीचे गिर गया, सारे अंडे टूट गये। ऐसी ही हालत इनकी हुई है। सरकार का इरादा तो ठीक था। कहते हैं ताश के बावन पत्ते होते हैं और उन से हर गेम खेली जाती है लेकिन इन बावन पत्तों के अलावा एक पत्ता और भी होता है और उस का नाम मैं नहीं लूंगा। वह किसी खास हेराफेरी की गेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने तो पूरी कोशिश की कि उस पत्ते से कोई खास गेम खेले और उस गेम के खेलने के लिये उस ने उस पत्ते का इस्तेमाल भी रक लिया लेकिन जब गेम खत्म हुई तो उस पत्ते को परे फेंक दिया। इन हालात तें मुझे यह कहना पड़ता है कि जमहूरियत के अन्दर अगर कोई जैजिस्लेटर जो जनता का विश्वास लेकर आता है इस प्रकार

प्रजातन्त्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह बहुत दुख की बात है। मुझे चंकि इस बात का बहुत दुख था और है इसलिये मैंने इस बात का जिक्र किया है। मुझे उनसे तैसे हमदर्दी है और हम उनका स्वागत करेंगे अगर वह यहां वापस आकर सही मायनों में हमारे साथ मिलकर जमहूरियत की रक्षा करेंगे। स्पीकर साहब, मैं अर्ज करता हूं कि सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट में अपनी तरफ से बहुत अच्छी बातें कही हैं क्योंकि सरकार जो काम करती है उसके लिये चाहती है कि उसका प्रचार होना चाहिये और उसे खांड चढ़ी गोली की तरह दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी बात होती है वह कितनी अच्छी है उसे देखने का म्यार यह है कि उससे लोगों को कितना फायदा हुआ है और होता है। जनता सरकार को बनाती है और वह सरकार से आशा रखती है कि वह उसकी भनाई के काम करे। उससे जनता को कितना लाभ होता है यह देखने की बात होती है। यहां पर सोशलिज्म के बहुत नारे लगाये जाते हैं कि हम गरीबी हटायेगे और गरीबी हटाने की बहुत बातों का इस गर्वनर एड्रैस में शुरू में ही काफी जिक्र किया गया है लेकिन इस सरकार ने जितने काम किये हैं उन से हमें जनता को क्या मिला है यह देखने वाली बात है। हम मान लेते हैं कि सरकार ने बहुत काम किया होगा और सरकार का फर्ज भी है कि वह काम करे हर सरकार यह काम करती है चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या जनसंघ की हो या और किसी भी पार्टी की हो। हर सरकार का जिसे जनता बनाती है चाहे वह किसी भी पार्टी की ही यह फर्ज होता है सड़कें बनाये लोगों को पानी दें

और दूसरे लोक भलाई के काम करे लेकिन इस करने में देखने वाली बात यह है कि यह जो काम हुआ उससे जनता को कितना लाभ हुआ है, कितनी गरीबी हटी है और कीमतें कितनी कम हुई है। अब आप देख ले कि यह जो इन्होंने बताया है कि यह किया वह किया उसका लाभ क्या हुआ हैं कीमतें आसमान को छूती दिखाई देती है और जहां तक गरीबी हटाने की बात है तो गरीबी बढ़ी ही है घटी नहीं है। सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी बढ़ी हैं। मैं तो कहता हूं कि न सिर्फ गरीबी बढ़ी हैं बल्कि गरीब तो इलिमीनेट होते जा रहे हैं और गरीब बीचसे हटते जा रहे हैं और गरीब कोई रहेगा ही नहीं अगर इसी तरीके से ये सरकार चलती रही और काम करती रही। सरकारी रिपोर्टस यह कहती है कि कीमतें बढ़ रही है और अनएम्पलायमेंट बढ़ रही है। आप देखें बेकारी का यह हाल है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज के सामने डाक्टर इन्जीनियरज ओर ग्रेजुएटस लाइनें लगाये खड़े मिलते हैं। नौकरी नहीं मिलती रोजगार नहीं मिलता। **(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)** इस सरकार ने इस एड्रैस के अन्दर बड़ी खुशनुमा बातें कहीं हैं कि बहुत प्रगति के काम किये हैं लेकिन सरकार की प्रगति की बात तभी नजर आयेगी अगर जनता को रिलीफ मिलता। तरक्की हुई है प्रगति हुई है लेकिन किन चीजों में? लैकस बनाने में जहां पर कि अमीर लोगों के लिये आरामोआयश के सामान मुहैया किये जाते हैं। रैस्ट हाउसिज को एयर कंडीशन करने ओर शराब की दुकानें खोलने में प्रगति की गयी है। लेकिन अब प्रगति की जो सबसे ज्यादा बात की जाने

वाली है ओर जिसकी चर्चा हो रही है वह है अनाज के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में ले लेने की और इस बात का इस एड्रैस में भी जिक्र किया है। ऐसा करने से कितनी कम्प्लीकेशनज पैदा होगी और हरियाणा की जनता को इससे क्या रिलीफ मिलने वाला है यह देखने वाली बात है। सरकार के जो काम होते हैं उनके बारे में सब जानते हैं। राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलता। अब तो हर जगह मिल सकता है और खुली मार्किट में मिलता है लेकिन जब इस पर सरकारी कंट्रोल जैसे यह चाहते हैं हो जायेगा तो देखना क्या हालत होती है। फिर सरकार के पास इस समय अनाज को रखने का कोई इन्तजाम नहीं है। किसान को अपना सारा अनाज इनके पास मार्किट में लाना पड़ेगा, अनाज के भाव मुकर्रर होंगे, सरकार सस्ते भाव पर किसानों से अनाज लेकर मंहगें भाव पर लोगों को बेचेगी फिर इस अनाज को लोगों को सप्लाई करने के लिये अनाज एक जगह से दूसरी जगह से जाने के लिए कभी गाड़ियां नहीं होगी और कभी कुछ नहीं होगा और अनाज लोगों तक नहीं पहुंचेगा। यह सरकार तो सारी जरूरियाते जिन्दगी अपने हाथ में लेकर जनता की बोलने की ताकत को खत्म करना चाहती है। सिवाये इन बातों के सरकार ने कोई और प्रगति नहीं की है –

**उपाध्यक्षा:** आप चेयर को एड्रैस करें। यह पब्लिक मीटिंग नहीं है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह हरियाणा के दुर्भाग्य की बात ही मैं कह सकता हूँ कि यहां पर एक आजकल टापिक चल रहा है जिसका चौधरी दल सिंह ने जिक्र किया है और वह है टीचर एजीटेशन के बारे में। आज सारे हरियाणा में टीचर्स की एजीटेशन चल रही है अरे आज यह टापिक आफ दि डे है। हरियाणा की सारी जनता को टीचर्स के साथ मुकम्मल तौर पर हमदर्दी है। अगर उसका प्रमाण आपने देखना हो तो आप किसी भी गली कूचे में चले जाये, किसी अखबार को उठाकर देख लीजिए या पार्लियामेंट की कार्यवाही को देख लीजिए, आपको एक ही चर्चा सुनने को मिलेगी कि हरियाणा सरकार ने टीचर्स की जायज मांगों को दबाने के लिए जिस तरीके से अत्याचार किया है, शायद पिछले 100 साल की तारीख के अन्दर ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलेगी। अगर इससे आगे भी देखा जाए तो भी आपको ऐसे जुल्म नहीं मिलेंगे। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जो गैर-मुल्की शासक था जो हिन्दुस्तान पर अपनी हकूमत बनाये रखने के लिए जनता पर अत्याचार किया करता था। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछता हूँ कि वह कौन सा तरीका है, जिसके द्वारा कोई भी पीड़ित वर्ग अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है। वह कौन सा तरीका है जिससे वह सरकार तक अपनी मांगे रख सकता है। प्रजातन्त्र के अन्दर लेबर कानून बना रखे है और इन कानूनों के अन्दर उनको हक दे रखें है। कोई भी वर्ग अगर असन्तुष्ट हो और वह वर्ग अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए सरकार से बातचीत करने

के लिए कहे तो कानून के तहत ताननी चाहिए। चार सालों से टीचर्ज बातचीत करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। कानून के अन्दर, विधान के अन्दर उनका यह हक है कि वे स्ट्राइक कर सकते हैं, भूख-हड़ताल कर सकते हैं, अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार की तवज्जो दिला सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि टीचर्ज ने क्या गुनाह किया है? शायद इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वह सरकार की तवज्जो दिलाने के लिए स्कूल जाएंगे लेकिन पढ़ायेगें नहीं, आराम से बैठेगें। यह एलान होने के बाद जिस तरीके से टीचर्ज के साथ व्यवहार किया गया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ने उनसे किस पाप का बदला लेना था। सारी आफिशियल मशीनरी-डिप्टी कमीश्नर से लेकर थानेदार तक जितनी भी सरकारी मशीनरी थी, अपना सारा काम छोड़ कर स्कूलों के अन्दर गये और वहां जाकर टीचर्ज की बेइज्जती की गई, उनको घसीटा गया, जेल में ठूस दिया गया। मैं एक व्यक्ति का जिक्र करूंगा। एक अफसर साहब जो सरकार की वफादारी का दम भरते हैं, वे एक स्कूल में गए। वहां एक लेडी टीचर बैठी थी। ये उनको कहने लगे कि पढ़ाओं उन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगें क्योंकि हमारी यूनियन का फैसला है। इस पर उस अफसर ने जो शब्द कहे वे ऐसे हैं - 'इस डंडे से मिर्च लगाकर.....आगे आप ही फिकरा पूरा कर लीजिए कि उसने क्या कहा होगा। आगे आप ही समझ लीजिए।

**एक माननीय सदस्य:** ये बातें गलत ढंग से कही जा रही हैं, इनकी ठीक ढंग से बताया जाए, हमारी सरकार इन्क्वायरी करेगी। यह गलत बात है.....

**चौधरी राम लाल वधवा:** सरकार इन्क्वायरी करना चाहती है तो मैं उस अफसर का नाम भी बता दूंगा और साबित भी कर दूंगा। टीचर्स मांगते क्या है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरे मुलाजमों की तरह इनको भी डी0ए0 दें, कौन सी यह अनजस्टिफाईड बात है। जब सरकार ने टीचर्स की तबदीली की पालिसी बनाई थी तो इनको वह फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिये जो दूसरे महकमों के मुलाजमों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिये मिलती है। इनके लिये रिहायश का इंतजाम होना चाहिये दूसरी सहूलियतें मिलनी चाहिये.....  
(व्यवधान).....डिप्टी सपीकर साहिबा, शायद ही इतिहास में ऐसी मिसाल होगी जिसमें हजारों के करीब टीचर जेल गये हो। आज आप देख रहे हैं कि 11 हजार के करीब टीचर जेलों जा रहे हैं। शायद ही पिछले समय में किसी तहरीक में इतनी तादाद रिकार्ड की गई हो। कोई 400 या 500 टीचर्स रोज जेल जा रहे हैं, लोग जेलों में गये होंगे लेकिन इतनी बड़ी एजीटेशन जिससे किसी आदमी को यह खतरा हो कि मेरी सर्विस चली जायेगी, मेरा बहुत बड़ा नुक्सान हो जायेगा, इसके बावजूद भी एजीटेशन कर रह है ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें कितनी तकलीफ थी, उनको कितना दुख था और



उनकी मांगे कितनी जायज है जिसके लिये वे अपनी सारी उम्र की नौकरी और अपने परिवार को कुर्बान कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गवर्नर एड्रैस में टीचरों का जिक्र लॉ एंड आर्डर के अन्दर, जहां पर डाहुओं का जिक्र किया गया है, वहां किया है। टीचरों के लिये पहली लाईन लिखने के बाद यह लिखा है कि इतने डाकू पकड़े गये। यानि वे लोग जो इस देश की नसल को बनाने वाले हैं, जो शिक्षा लेकर आज हम मिनिस्टर बने हैं, एम0एल0ए0 बने हैं, जज बने हैं और राष्ट्रपति बने हैं, उन लोगों को गवर्नर एड्रैस के अन्दर डाकुओं के साथ लिख दिया गया है।

**उपाध्यक्षा:** कौन सी सतर पर लिखा है?

**चौधरी राम लाल वधवा:** यह पेज 18 पर है।

**चौधरी भजन लाल:** टीचरों को डाकू नहीं कहा है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** मैंने कहा है उससे अगली लाईन में डाकुओं का जिक्र किया गया है। जो इसमें लिखा है उसको पढ़ देता हूँ, अगर गलत हो तो मुझे बता दें –

“The law and order situation remained under control. An unfortunate trend noticed this year was an attempt on the part of a section of the teachers to spread indiscipline and foment trouble. The teachers of private colleges started an agitation but better counsel prevailed and the agitation was called off. A section of teachers of

Government Schools also attempted a stay-in-strike but except in a few pockets. The response was poor. The situation was dealt with firmly and all trouble creators were either arrested or their services dispensed with. It was very heartening to find the students acting with a sense of responsibility. They generally refrained from taking the law and order in their own hands and did not succumb to unhealthy influences and pressures. The crime against person showed general improvement. Two important gangs of dacoits were rounded up leading to the detection of two serious dacoities committed in Jind and Rohtak and a number of truck robberies committed in the Districts of Rohtak and Gurgaon.....”

**चौधरी भजन लाल:** ठीक है, डाकुओं का जिक्र आगे किया है, यह नहीं कहा कि टीचर डाकू है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** यह एक ही पैरे में लिखा हुआ है.....

**कई माननीय सदस्य:** एक पैरे का मतलब यह नहीं कि टीचरों को डाकू कहा है .....(हंसी).....

**चौधरी राम लाल वधवा:** ला ऐंड आर्डर के अन्दर जहां किमिनल का जिक्र है, वहां टीचर का जिक्र किया गया है, मैंने यह अर्ज किया है।

**उपाध्यक्षा:** किमिनल के साथ लगने से यह मतलब नहीं कि उनको कहा गया है। It is wrong.

**Chaudhri Partap Singh Daulta:** There is a specific paragraph in the Governor's Address relating to education. This agitation has not been dealt with in that paragraph. It has been referred to in a paragraph, which pertained to law and order and if an hon. Member points it out to the Government, there is nothing wrong in it. He should not be disturbed. It is every body's democratic right to say what he likes. After all, we have come in the House with different views. I have my own views. I will contradict him like anything in my own way. But it is wrong to disturb him.

**चौधरी राम लाल वधवा:** जो दौलता साहब ने कहा है, यही मैं आगे सजैस्ट करने वाला था। जहां टीचर्स का जिक्र है वहां इसको मैन्शन करना चाहिये क्योंकि इसका ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं था। ला-ऐंड-आर्डर की हालत में आगे बताउंगा कि आज इसकी हरियाणा में क्या हालत हो रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, टीचर्स के साथ बुरा सलूक करने के लिये क्या-क्या तरीके अपनाये गये इसका जिक्र भी करना चाहता हूं। दफा 107 और 151 का गलत प्रयोग किया गया। इसका मतलब यह है कि कोई शरीफ शहरी, कोई शरीफ आदमी, अगर सरकार के आगे झोली फौलाकर अपनी मांग रखता है तो सरकार के पास एक ही तरीका है कि दफा 107 और 151 का प्रयोग करके जेल भेज देगी। इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिये। टीचर हमारी आने वाली नसल को पढ़ाने के लिये है। आज बच्चों के इम्तिहान शुरू है। उनका नुक्सान हो रहा है। सरकार कितना दम भरती है, इसने रिपोर्ट में लिख दिया है कि एक सैक्शन ने

स्ट्राईक की है लेकिन सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता। आज तालीम बिल्कुल ठप्प है। स्कूल बिल्कुल ठप्प है, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। कोई टीचर सरकार के डर के मारे, उसकी दमन की चक्की के अन्दर पिसने से बचने के लिये स्कूल के अन्दर भले ही जा रहा हो लेकिन प्रैक्टिकली हरियाणा में स्कूलों के अन्दर तालीम बिल्कुल ठप्प है। सरकार कितना ही प्रोपेगंडा कर ले कि एक सैक्शन की स्ट्राईक है या टीचर्स के एक सैक्शन ने स्ट्राईक की है लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। आज पूरे टीचर्स एक साथ हैं और हरियाणा के पूरे लोग उनसे म्पिथी रखते हैं। सरकार से मैं यह अनुरोध करूंगा, यह अपील करूंगा कि ऐसी कम्युनिटी के साथ, ऐसे सैक्शन के साथ इस तरीके का बर्ताव जो है वह ठीक बात नहीं है। मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि उनकी मांगें जायज हैं, उन पर यह हमदर्दी से गौर करें। हम तो समझते थे कि सरकार ने टीचर्स के साथ जो बातचीत शुरू की वह एकबहुत अच्छी बात है लेकिन आज सुबह की अखबारों में फिर आया कि बातचीत टूट गई है। यह बड़े दुख की बात है और मैं सरकार से सारे हाउस की तरफ से अपील करूंगा कि उनकी जायज मांगें हैं, उनको पूरा किया जाये।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात का उल्लेख करूंगा जो एक बड़ी तरक्की की बात सरकार ने बताई है। वह बात ट्रांसपोर्ट नैशनेलाइजेशन के बारे में है। यह कहा

गया है कि सरकार ने कम्पलीट नैशनेलाईजेशन कर ली है। मैं सरकार से आपके द्वारा एक बात पूछना चाहता हूँ.....

**उपाध्यक्षा:** आपने काफी समय ले लिया है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी तो दस मिनट भी नहीं हुए। अभी तो मैंने एक ही टोपिक को डील किया है।

**उपाध्यक्षा:** 25 मिनट के करीब आपको बोलते हुये हो गये है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** दूसरे मैबरान ने काफी इंटरप्ट किया है। मुझे तो केबल दस मिनट ही मिले है।

**उपाध्यक्षा:** कृपया जल्दी खत्म करें।

**चौधरी राम लाल वधवा:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, अर्ज यह है कि स्कीम के अन्दर यह कहा गया है कि ऐडिक्वेट और ऐफिशिएंट सर्विस सरकार देगी। सर्विस कितनी ऐडिक्वेट है इसके बारे में तो क्वेश्चन आवन में पता लग गया। उसके अन्दर सरकार ने यह एडमिट किया है कि ओवरलोडिंग हो रही है। सरकार ने एडमिट किया है कि ट्रिप मिस हो रहे है। सरकार ने यह एडमिट किया है कि ब्रेक-डाउन हो रहे है। और भी बहुत सी बातें सरकार ने मानी है। जितना सरकार ने माना है अगर उससे ज्यादा देखना हो तो बस स्टैन्डज पर चले जाइये, रोड्ज पर चले

जाइये। रोडज पर जाते हुये कोई दिन खाली नहीं होगा जब आपको दो तीन बसें खड़ी न मिलें। ऐडिक्वेट सर्विस देनी थी तो सरकार को पहले सोचना चाहिये था कि बसें हमें पूरी मिल सकेंगी या नहीं। जहां तक ऐफिशिएंसी का ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कौमन मेन से जाकर पूछिये कि बस स्टैन्ड पर उसकी क्या हालत होती है। लम्बे स्टेशनज के टिकट दिये जाते हैं। छोट स्टेशनज के टिकट लेने के लिये लोगों को सुबह नौ बजे से शाम के चार बजे तक बस स्टैन्डज पर खड़े रहना पड़ता है लेकिन उनको फिर भी टिकट नहीं मिलते। इसके अलावा ओवरलोडिंग की तो हद ही हो गई है। कल सरकार मान रही थी कि ओवर लोडिंग होती है लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ ओवरलोडिंग ही नहीं होती बल्कि ओवरलोडिंग के साथ जबरदस्ती की जाती है। लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बसों के अन्दर भरा जाता है। लोग मजबूर हैं क्योंकि और कोई जराय उनके पास आने जाने का है नहीं। आधे से ज्यादा बसें पुरानी है। टायरज भी इनके पास नहीं है। बसों का टाईम हो चुका होता है लेकिन कहा जाता है कि बस टायर बदल रही है। अगर बस चल पड़ती है तो मशीनरी चूंकि उसकी खराब होती है इसलिये रास्ते में वह खड़ी हो जाती है। आज बस स्टैन्डज के ऊपर जितनी टिप-टाप है, रैस्टोरेन्टस ,खुले है, वे सब अमीर आदमियों के लिये हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा सरकार गरीबों के लिये क्या कर रही है? आम आदमी से वह कर वसूल करती है, बजट के अन्दर उसका मेन हिस्सा है लेकिन गरीब आदमी को मिल क्या

रहा है, यह देखने की बात है। डी-लक्स बसें ज्यादा चलती हैं। एयर कंडीशन्ड बसें चलाने के लिये सरकार के पास रूपया हैं। अमीर आदमियों के मनोरंजन के लिये, ऐन्टरटेनमेंट के लिये पिकचर दिखाई जा रही है एयर कंडीशन्ड बस के अन्दर जो चार बजे चण्डीगढ़ से दिल्ली को और चार बजे दिल्ली से चण्डीगढ़ को चलती है। जिन लोगों की जेबों से रूपया निकाला जाता है उन लोगों को बैठने के लिये बसें नहीं हैं, सीट्स नहीं हैं लेकिन अमीर आदमियों के लिए, बड़े-बड़े लोगों के लिये ट्रांसपोर्ट के अन्दर सहूलियत मुहैया की जा रही हैं। बस स्टैन्ड अमीर आदमियों के लिये तो सरकार अपने रैस्टोरैन्ट खोलती है लेकिन आम आदमी के चाय और खाने पीने की चीजें मुहैया करने वाली दुकानें नीलाम की जाती हैं। नीलामी के जरिये लाखों रूपया सरकार रेवैन््यू के अन्दर ले जाती है। उसका नतीजा यह होता है कि आपने चने लेने हो तो आपको पानी मिलेगा, चना नहीं मिलेगा, चाय लेनी हो तो पानी और चाय की पत्ती होगी, दुध नहीं होगा और 20पैसे का कप 40 पैसे में गरीब को मिलेगा। सरकार ने ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीयकरण की जिम्मेदारी ली है तो इसे चाहिये कि यह जनता ऐडिक्वेट और ऐफिशिएंट सर्विस भी मुहैया करे।

इसके बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक और चीज का जिक्र करूंगा। औगमेंटेशन कनाल करनाल के अन्दर बनी हैं आज भी क्वेश्चन अवर के अन्दर एक सवाल के जवाब असलियत को छुपाने की कोशिश की गई। असलियत यह है कि वहां जो

ट्यूबवैल्ज लगे है उनसे करनाल के अन्दर पानी नीचे से और नीचे चला जा रहा है और इस वक्त ये ट्यूबवैल्ज चलने के बाद आधे मील के टुकड़े के अन्दर जितने भी खेत है उनके अपने ट्यूबवैल्ज पानी देने के नाकाबिल हो रहे है। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस तरीके से यह औगमेंटेशन कैनाल बनी है और उस पर जो 13 करोड़ रूपया खर्च हुआ है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यह नहर कुछ दिनों के बाद ही करनाल के पास टूटी और उसके परिणामस्वरूप लाखों रूपये की फसल बरबाद हुई और लोगों का नुक्सान हुआ। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस 13 करोड़ के अन्दर कई करोड़ों रूपयेका घपला हुआ है। वह सरकार ने किया हो या किसी आफिसर ने किया हो उसकी जुडीशियल इंक्वासरी होनी चाहिये। इसमें सीमेंट की बजाय रेत इस्तेमाल हुई है। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बारिश शुरू होने के बाद इस नहर के किनारे ओर यह नहर किस तरीके से टूटेगी यह उस समय पता लगेगा। मैं इस बात की मांग करता हूं कि यह जो 13 करोड़ रूपये उसके ऊपर खर्च किये गये है उसके अन्दर चूंकि घपला हुआ है इसलिये इसकी जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये।

**उपाध्यक्षा:** चौधरी साहब, आपका टाईम अब खत्म हो गया है।



**चौधरी राम लाल वधवा:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, कम से कम मुझे आधा घंटा तो दें। मैं। एक पौलेटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूं इसलिये मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिये।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्हे टाईम बहुत थोड़ा मिला है। अभी तो इन्हें बोलते हुये केवल पन्द्रह मिन्ट हुये है।.....(विघन).....

**उपाध्यक्षा:** आप जन्दी जन्दी दो मिनट में खत्म कीजिये, दूसरे मैबर साहिबान ने भी बोलना है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** जहां तक बिजली का सवाल है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बात का बहुत शोर हुआ है कि बिजली की तारें हमने सारे हरियाणा में फैला दी। ठीक है, सरकार ने यह काम किया है। करना भी चाहिये था लेकिन बिजली की तारों का लोग क्या करेंगे। बिजली की तारों का फैलाव करनेसे पहले सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये था कि इन बिजली की तारों के अन्दर जो बिजली आनी है वह कहां से आयेगी और कितनी मात्रा में आयेगी। पानीपत थर्मल प्लांट चार साल से बन्द है। सरकार ने यहां कोई जैनरेटर नहीं लगाया। इस तरीके से सरकार का बिजली के फैलाव की योजना बनाना घोड़े को गाड़ी के पीछे जोतने वाली बात है। सरकार की यह कोई अच्छी स्कीम और अच्छी योजना नहीं है। इसे पहले यह सोचना चाहिये था कि बिजली पैदा करने साधन क्या होने

चाहिये। उसके बाद सरकार को इन बिजली की तारों का फैलाव करना चाहिये था।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इस बारे में पिछले सेशन में यह आया था कि देहात के दलाकों में भी इंडस्ट्री लगाई जायेगी लेकिन सरकार सिवायें कागजों पर लिख देने के और कुछ नहीं कर रही है। कागजों पर लिख देते है कि हम यह कर रहे है, वह कर रहे है लेकिन सरकार के पास कोई डैफिनेट योजना नहीं है जिसके जरिये से गांव में इंडस्ट्री लगाने का प्रचार किया हो या लोगों के सामने कोई स्कीम वगैरह रखी हो जिससे देहात के लोग इंडस्ट्री की ओर आकर्षित हो।

मैं एक मिसाल देता हूं जापान की। जापान की एक सीको-रीको फर्म है। उसने सरकार से घड़ियों का कारखाना लगाने की बात की और सरकार से कहा कि जहां हम कारखाना लगायेंगे उसके गिर्द पचास गांवो को भी इंडस्ट्रीलायज करने की जिम्मेदारी लेते है। उन्होने यह किया कि एक छोटी सी मशीन हर गांव के अन्दर दी और सरकार ने उसके लिये रूपया दिया। गांव के लोग फालतू वक्त में पुर्जे बनाते है। शहर के अन्दर मेन फैक्ट्री है उसमें दे आते हैं फैक्ट्री में घड़ियां मैनुफैक्चर हो जाती हैं इसी तरीके से आज हरियाणा के अन्दर फरीदाबाद में जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है चाहे वह ट्रैक्टर की फैक्ट्री है या कोई और है , सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये।

उन बड़े-बड़े इंडस्ट्रीजिस्ट्स को यह कहना चाहिये कि छोटे-छोटे पुर्जे देहातों के अन्दर बनवाये जाये। अगर दो या चार करोड़ रूपया लोन सरकार ने देना है तो उससे छोटी-छोटी मशीनें लेकर देहातों के अन्दर दी जायें। अब तो देहातों में खेती भी कम हो रही है क्योंकि भूमिसुधार का कानून भी पास हो गया है। आज किसान के पास इतनी भूमि नहीं है कि वह अपना गुजारा कर सके। इनको काम प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस काम को चला सकता है। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। खाली कागजों पर रिखल देने से और ऐलान कर देने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा एक पिछड़ा हुआ प्रांत है। उसके देहातों के लोगों को तो यह भी नहीं पता कि पैसा कहां से मिलता है। वे दफ्तरों के अन्दर दाखिल होने से भी घबराते हैं। उनको यह भी पता नहीं कि शहरों के अन्दर इंडस्ट्री के दफ्तर हैं और कर्जा लेने से कोई इन्डस्ट्री शुरू होती है। पंजाब स्टेट एंड टू इंडस्ट्रीज ऐक्ट के अन्दर, फाइनेन्शियल कारपोरेशन के द्वारा कर्जा दिया जाता है। आज इन्डस्ट्री की हालत यह है कि दो-दो साल तक आबजैक्शन लगते रहते हैं, लाला फीता चलता है। फाईल दफ्तरों में चलती ही नहीं है जब तक क्लर्क से लेकर ऊपर तक राजी न हो जायें। इंडस्ट्री लगाने वाला बेचारा जमीन लेकर, मशीनरी का आर्डर देकर दो-दो साल तक बैठा रहता है लेकिन कर्जा नहीं मिलता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि हरियाणा के अन्दर इंडस्ट्री पनप ही नहीं रही है। इलैक्ट्रिक गुड्स इन्डस्ट्रीज की यह

हालत है कि उनको चादरें ही नहीं मिलती है। ये चादरें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और टाटा वाले बनाते हैं लेकिन वे उन लोगों को दे ही नहीं रहे हैं। पहले एक प्रायरिटी कमेटी बनी हुई थी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को चादर देने में परैफैन्स देती थी। लेकिन अब वह प्रायरिटी कमेटी भी खत्म कर दी है। छोटी-छोटी इन्डस्ट्री वालों को हिन्दुस्तान स्टील और टाटा वाले चादरें देते नहीं हैं, वे बड़े-बड़े इन्डस्ट्रीयलिस्टम को देते है, वे ब्लैक में गाड़ियों की गाड़ियां ले आते हैं। अब उसका नतीजा यही हो रहा है कि हरियाणा में जो इलैक्ट्रिक गुड्स की फ़ैक्ट्रीज लगी हुई थी उनका काम पिछले तीन मास से ठप हो रहा है। यह सब सरकार की गलत पालिसी की वजह से हो रहा है। इस बात की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हरियाणा अगर खड़ा हो सकता है तो इन्डस्ट्रीज पर खड़ा हो सकता है। यदि इन्डस्ट्रीज की हालत को सुधारना है तो उन्हें कर्जा वक्त पर मिले, उन्हें मैटिरियल वक्त पर मिले, उन्हें बिजली वक्त पर मिले। इस तरीके से ही हरियाणा इन्डस्ट्रीयलाइज हो सकता है और सारे हिन्दुस्तान में जिस प्रकार से हरियाणा ने खेतों में नाम कमाया है उसी प्रकार से इन्डस्ट्री में भी सबसे आगे आ सकता है। (घंटी)

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं लेबर मिनिस्टर साहब को एक दो सुझाव दूंगा क्योंकि सही मायनों में जम्हूरियत वही है जहां अपोजीशन क्रिटिसाइज करे, उसके साथ साथ कुछ सुझाव भी दे। इसलिए मैंने जितनी भी बातें रखी है उनके बारे में

डिपार्टमेंट वाइज कुछ सुझाव भी देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। एक दो सुझाव मैं डिपार्टमेंट वाइज देना चाहता हूँ। जहां तक हरियाणा की लेबर का ताल्लुक है वह सबसे ज्यादा तंग हो रही है। जो लेबर कोर्टस बनाई गई हैं या पेमेंट आफ वेजिज एक्ट है या मिनीमम वेजिज एक्ट है उसकी पार्वज खास-खास अफसरों को दे रखी है। उससे लेबरर्ज को काफी तकलीफ होती है। इसलिए मैं लेबर मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करूंगा कि जो ऐ लेबर अफसर को मिनीमम वेजिज एक्ट की और पेमेंट आफ वेजिज एक्ट की पावर दे रखी हैं और कुछ पार्वज इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट के अन्दर लेबर ट्रिब्यूनलज को हैं, कुछ लेबर कोर्टस को हैं, इन सब को एक जगह इकट्ठा करना चाहिये। इसी तरह से वर्कमैन ऐंड लेबर कम्पनसैशन एक्ट की पार्वज भी किसी और को दे रखी है। कहने का मतलब यह है कि एक मुलाजिम को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है ओश्र उनके जो वकील हैं वे जेबें भरते हैं। वे बार-बार तारीखें लेते हैं। सरकार को चाहिये कि वे एक ही कोर्ट बनाये और ये मूविंग कोर्टस बन्द की जायें। हरेक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज लगा दिया जाये या कोई रिटायर्ड जज लगा दिया जाये। जितने भी लेबर ऐक्टस हैं, चाहे वह पेमेंट आफ वेजिज एक्ट है, चाहे वह मिनीमम वेजिज एक्ट है, चाहे वर्कमैन ऐंड लेबर कम्पनसैशन एक्ट है, चाहे इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इन सब को कनसोलिडेटिड कर देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा आप हैरान होंगी कि एक-एक एक्ट के अन्दर

अलग-अलग हाजरी रजिस्टर हैं। हाजरी के लिए अलग अलग तरीके के रजिस्टर हैं।

इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि इन सारे एक्टस को इकट्ठा करके एक वाहिद कानून बना दिया जाये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एक लेबर कोर्ट भी बना दी जाये ताकि लेबरर्ज की मदद की जा सके और उनकी जो छुट्टी जाया होती है और टाईम जाया होता है वह भी बच सके। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं अभी समाप्त करता हूं केवल एक सुझाव और देना चाहता हूं। करनाल के अन्दर इम्पूवमेंट ट्रस्ट भी बना हुआ है, अब वहां पर अरबन अस्टेट की ऑफिस भी बना दिया है, टाउनप्लानर का भी बना दिया है और एक डिवैलपमेंट आफ कालोनीज एक्ट के तहत भी ऑफिस बना है। इस तरह से लोकल बॉडीज के तीन-चार दफतर वहां हैं। इतने अदारे खड़े कर दिये, एक म्यूनिसिपल कमेटी है, इम्पूवमेंट ट्रस्ट है, टाउन प्लानर है, अरबन अस्टेट हैं यानी अलग-अलग चारों चौधरी बन गये हैं। आपस में खींचातानी हो रही है, काम ठीक तरह से हो नहीं रहा है। इम्पूवमेंट ट्रस्ट ने कोई स्कीम बनाई है तो टाउन प्लानर को वह मंजूर नहीं है। टाउन प्लानर ने बनाई है तो अरबन अस्टेट वाले औब्जैक्शन लगा देते है कितने ही महीनों और सालों से स्कीमें यूं ही पड़ी हुई है, न कोई सड़कों का इन्तजाम है और न ही कोई पानी का इन्तजाम है। सिवरेज का भी कोई प्रबन्ध नहीं

है। आज वहां सात-आठ महीने तो टाउन प्लानर को आये हुये हो गये है। (घंटी).....

**गृह मंत्री (श्री के०एल०पोसवाल):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, क्या 25 मिनट रामलाल जी को और दे दिये है?

**चौधरी रामलाल वधवा:** होम मिनिस्टर साहब आप तो सारे होम डिपार्टमेंटक के मालिक हैं, इसलिये आपको तो सारी बातें सुननी चाहिए। वहां पर लूट मचा रखी है और हर कोई अपनी अपनी जेबें भरने की स्कीमें बनाता है। जो भी वहां स्कीम बनती है वह गरीब आदमी को इफ़ैक्ट करती है। अगर वहां की सारी स्कीमों को देखा जाये तो बड़े लोगों को निकाल दिया गया है और गरीब लोगों की जमीन ले ली गई है। चारों और बड़े-बड़े जमींदारों के साथ सौदा किया हुआ है उनको छोड़ दिया गया है।(घंटी).....

इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया। इस एड्रैस के अन्दर एक जबरदस्त कमी यह है कि शाह कमीशन, अबोहर और फाजिल्का का कोई जिक्र नहीं। (घंटी).....सरकार को वे इलाके ट्रांसफर कराने चाहियें। इस एड्रैस में जो कुछ भी कहा गया है वह सब दिखावा है। मैं इसका विरोध करता हुआ और सबका धन्यवाद करता हुआ स्थान लेता हूं।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा): डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल से गवर्नर साहब इस पर बहस चल रही है और प्रायः यह देखने में आया है कि हर बजट सेशन के पहले दिन साहब का एड्रेस होता है। मैं यह समझता हूँ कि यह एक रस्मी एड्रेस होता है और उस के तहत कल से गवर्नर साहब के एड्रेस पर बहस हो रही है और इसके उपर आज भी चल रही हैं। काफी ज्यादा साथियों ने उधर ट्रेजरी बँचिज से और इधर अपोजिशन से बोलने में भाग लिया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा मुझे अफसोस है कि सिर्फ गवर्नर साहब एड्रेस पढ़ने से समाजवाद और सोशलिज्म की बात का जो उधर बैठने वाले हमारे साथी करते हैं और बार-बार इस बात को कहते हैं कि समाजवाद ला रहे हैं और डिसपैरेटी को ला रहे हैं और सबको हम एम्प्लायमेंट दे रहे हैं, ये तीन चार बातें आमतौर पर कही हैं। इस एड्रेस से यह जाहिर होता है कि इन बातों को बिल्कुल भी मददेनजर नहीं रखा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहब ने पेज एक पर जो जिक्र किया है, मैं सबसे पहले उसको लेता हूँ। उन्होंने यह कहा है :

“The provision of drinking water, food and clothing, basic medical facilities, education and the removal of social inequalities are some of the matters which are engaging the constant attention of the Government.”

जंहा तक सोशल इन इक्वैलिटीज का सम्बंध है, वर्डज बड़े शानदार ढंग से लिखे हुये हैं। साहब के एड्रेस के पहले पेज पर यह लिखा तो अवश्य गया है लेकिन देखने में यह है कि



हरियाणा के अन्दर स्थिति डिफरेंट है। मैंने सुबह एक सवाल पूछा था जो रोड़ज प्रोग्राम के बारे में था। उसमें मुझे बताया गया कि 26 एस0डी0ओज0 और 258 टीयर्ज रोड़ज के कौश प्रोग्राम की बाबत लगाये गये थे जो कि अब तक कन्टीन्यू कर रहे हैं। साथ ही जो लोग दिहाड़ी करके रोटी कमाते थे और जिनको तीन या साढ़े तीन रूपया दिहाड़ी मिलती थी, उनकी तादाद हरियाणा में तकरीबन साढ़े तीन लाख थी। व लोग 30-1-1972 से अपने घरों में बेकार बैठे हैं, उनके लिये रोटी कमाने का कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं किया गया। ऐसा कहने से कि हमारी पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी है या घटी है, उन लोगों को नहीं मिल सकेगी। सवाल सिर्फ इस बात का है कि हम उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये हमें रूरल इन्डस्ट्रियलाईजेशन करना पड़ेगा। रूरल इन्डस्ट्रियलाईजेशन के लिये कोई नुमाया कदम गवर्नर साहब के इस कदम से जाहिर नहीं होता। आज देश के अन्दर इस बात की सख्त जरूरत है। जब तक इंडस्ट्रिलाईजेशन और ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तब तक मंहगाई रूक नहीं सकती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी गरीबों से हमदर्दी रखती हैं और उन्हें काफी नजदीक से देखती रहती हैं। मजदूरों की यह स्थिति है कि वे बेचारे भूखे मर रहे हैं। जिस आदमी को लगातार महीना काम न मिले और उसके पांच सात बच्चे हों और उधर एक रूपये 55 पैसे किलो आटा मिलता हो, आप कलेजे पर हाथ रखकर देखें, वह आदमी कैसे गुजारा करेगा। मैं यह बात बताये

बगैर नहीं रहूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अन्दर जिन्दल साहब, जोकि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और जिनकी पाईप फैक्ट्री शायद ऐशिया में नम्बर वन पर है, का एक गांव है। उस गांव में एक ऐसा गरीब हरिजन भी है जिसको दो-तीन दिन तक कोई रोटी नहीं मिली और यहां तक कि उधार भी नहीं मिला.....

..

**Shri Gulab Singh Jain:** On a point of order, Madam. Can he refer to a person who is not present in the House?

**Deputy Speaker:** He can mention like that.

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह केवल पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि एक एस्टैबलिशड प्रैक्टिस है कि गवर्नर का एड्रैस मेनली पोलिटीकल पालिसी, इक्तसादी और तरक्कीयाती बातों पर होता है। आगे बजट आयेगा। बजट पर इस तरह की स्पीच हो जाये। करैन्ट टापिक्स पर बोल लें।

**श्री अमर सिंह:** पहले पहल सन्त जी डिस्टर्ब किया करते थे, इस बार दौलता साहब ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया।

**Deputy Speaker:** Leave this to me. You continue your speech.

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि जब उसको दो-तीन दिन तक काम नहीं मिला और नही

उधार मिला तो उसने अपनी लड़की की कंठी देकर अपने पड़ोस से उधार लेना चाहा लेकिन उसको बाजरा भी नहीं मिला। तीसरे दिन जब उसका घर वाला किसी दूसरे काम से अपना प्रबन्ध करने के लिये गया हुआ था तो उसकी घवाली ने अपनी चूड़ी फोड़कर अपने बच्चों को पीसकर पिलानी चाही। इस तरह की स्थिति हरियाणा के अन्दर है। जहां तक पर-कैपिटा इनकम की फिगर्ज का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि फिगर्ज तो बहुत शानदार है। इसके अलावा जहां तक फूड-ग्रेन्ज और उनकी प्रोडक्शन की बाबत बतलाया गया है, इस बात में कोई शक नहीं है कि फूड-ग्रेन्ज की सरकारी दुकानें खोली गई है लेकिन अगर उनका सर्वे किया जाये तो यह पता चलेगा कि उनसे गरीबों को आटा नहीं मिलता। केवल चन्द आदमी ही वहां से आटा ले पाते हैं। जो कोई डिपो खोलता है, वह अपने चन्द आदमियों को आटा बेच कर बाकी आटा ब्लैक में बेचता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। मिनिस्टर साहब बेशक इसकी तहकीकात करवायें। बहुत सारे इस तरह के इग्जाम्पलज हैं जिनमें चन्द आदमियों को आटा देने के बाद बाकी आटा ब्लैक में बेचा गया है और कई जगहों पर तो सारा ही ब्लैक में बेचा गया है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाये। आज देहात के अन्दर एग्रीकलचरल लेबर और एग्रीकल्चरिस्ट को भी परेशानी है। न तो नहरों में पानी है, अगर पानी है तो बहुत ही कम है, जरूरत के मुताबिक नहीं है और नही बिजली पूरी मिलती है। आपको पता ही है कि बिजली की शोर्टेज चल रही है। आज किसान जो ट्युबवैल लगाये बैठा

है, वह इतना अन-सर्टेन हो गया है इलैक्ट्रिसिटी की बाबत, कि उसको इस कोई यकीन नहीं। उसको यह पता नहीं कि अगर इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने यह अनाऊंसमेंट कर दी कि दिन के 12 बजे बिजली मिलेगी, तो वाकई उस समय उसको बिजली मिलेगी भी या नहीं। वह बेचारा दिन के 12 बजे अपने ट्यूबवैल पर बैठ जाता है और रात को 12 बजे कहीं उसको बिजली मिलती हैं बहुत सारी जगहों पर तो किसान मजबूर होकर इस और सेचने लगे है कि बिजली से ट्यूबवैल चलाने की बजाय वह इंजन बदलकर तेल से चलायें जाये। अगर इन्जन एब जगह बदल यिे गये तो मैं समझता हूं कि इससे सरकार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। किसान तो हर वक्त धक्के में रहेगा ही क्योंकि इन्डस्ट्रियल सैक्टर वाले भी किसान की गर्छन पर पांव रखते है और अगर कोई दूसरा होता है तो वह भी किसान की गर्दन पर पांव रखता हैं। गवर्नर एड्रैस से भी यह इंडीकेशन मिलती है कि किसन से आबियाना, माल ओर कई किस्म का कौप टैक्स वगैरा लेने की बात चल रही है। मैं यह समझता हूं कि मंहगाई, टैक्सज लगाने से या इन बातों से दूर नहीं होगी। अगर मंहगाई को दूर करना है तो लाजमी तौर पर किसानों को ओर इन्डस्ट्रियलिस्टस को सहूलियतें देनी पड़ेगी। जब तक उनको सुविधायें नहीं मिलेंगी तब तक इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन और ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकेगी। जब तक इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन और ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तब तक लाजमी तौर पर मंहगाई इसी तहर से बदस्तूर बढ़ती चली जायेगी जिसका हमारे पास कोई इलाज

नहीं है। मैंने बहुत सारे गांवों में देखा है और आपको भी पता होगा कि एग्रीकल्चरल लेबर चा मजदूर हैं वे मोस्टली श्रू आउट दी ईयर बेकार है और लैंड सीलिंग एक्ट बनने के बाद तो तीस साल का मुजारा भी घर बैठा हुआ है। मुझे यह पता है, मेरे अिुत सारे साथी यहां वकील भी हैं, उनको भी पता है कि किसानों के दिमाग में एक बात आ गई और कितने ही लोगों ने बेनामी ट्रांजैक्शन की। जो 30 किल्ले का मालिक था उसने वह जमीन चार-चार, पांच-पांच जगह टुकड़े करके बेची जिससे स्माल होल्डिंग्स हो गई है। मैंने पिछली दफा लैंड सीलिंग बिल पर बोलते वक्त भी कहा था और अब भी बता रहा हूं कि इन स्माल होल्डिंग्स का पता 5-10 साल के बाद लगेगा जब हम इनसे बहुत तंग आयेंगे। सवेरे ट्रैक्टर की बाबत जिक् आ रहा था, मैं तो कहता हूं कि फिर टैक्टर लेने का कोई नाम नहीं लेगा। इतनी स्माल होल्डिंग्स हो जायेगी कि लोग एक-एक मिल्ले या डेढ़-डेढ़ किल्ले के मालिक बन जायेंगे और एग्रीकल्चरल लेबर की मांग में कमी हो जायेगी। इस तरह से जो आर्थिक ढांचा बन रहा है उसके बारे में मैं सरकार से यह कहूंगा कि उसको बदले। शुरू में यानी 1968 या 1969 में तो वक्त था जब एम0एल0एज0 बहुत बड़े हाथी बने हुये थे लेकिन आज तो वह बात नहीं है और सरकार बड़ी थम्पिंग मैजोरिटी में चल रही है। इसलिये बजाय इस बात के कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या कोई दूसरी चीजों पर पैसा खर्च किया जाये, यह पैसा लोगों की भलाई के काम में लगाये। मेरे से पहले बोलने वाले कई साथियों ने भी इस बारे में बताया है कि कुछ

एम0एल0एज0 को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स का चेयरमैन वगैरह बनाकर रखा हुआ है जिसकी वजह से एक्सचेंजर पर एडीशनल बर्डन है, इसलिये इसको दूर करना चाहिये। जब तक एग्रीकल्चरिस्टस को सहूलियतें और इन्सैन्टिवज़ नहीं देंगे और जब तक रूरल एरियाज में रूरल इन्डस्ट्रियलाईजेशन नहीं करेंगे तब तक जमीन पर बर्डन बना रहेगा। जब तक जमीन पर बर्डन न रहेगा तब तक एग्रीकल्चरल लेबर या तो लिटीगेशन में फंसेगा या फिर उस पर मार पड़ी रहेगी और इसका कोई हल नहीं होगा। इसके अलावा एक बर्निंग क्वेश्चन और है जिस पर मेरे कई साथी पहले से ही काफी रोशनी डाल चुके हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, टीचर्ज जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने समाज को बनाना है, सोसायटी को ऊंचा उठाना है उनके प्रति गुरु की भावना आज नहीं रही है। इसलिये आज समाज के अन्दर अनरैस्ट है, स्टूडेंट्स के अन्दर अनरैस्ट है, टीचर्ज के अन्दर अनरैस्ट है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि गुरु अपनी गुरु की ड्यूटी का पालन नहीं करता और विद्यार्थी अपने विद्यार्थी-पन का पालन नहीं करता जिसके कारण यह अनरैस्ट चल रहा है आज टीचर्ज की मांग चाहे वह गलत है या सही है इस बात को सोचने का सवाल नहीं है। आज हो यह रहा है कि अध्यापक शिक्षा के मन्दिर में बैठकर विद्या देता है, शिक्षा देता है उसको एक अनपढ़ सिपाही उस ग्रेजुएट टीचर को, उस डबल एम0ए0 शिक्षक को गांव के लोगों के सामने पीटता है तो उस गुरु के

प्रति कैसे लोगो में आदर की भावना कायम रह सकती है। विद्यार्थियों में भी गुरु के प्रति आदर और सम्मान के विचार नहीं रहेगें। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान का रूप बदलती है और इसी भावना को लेकर बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। गांव के लोगो को पता है कि उन्होने अपना पेट काटकर स्कूल बनाये है ओर अपनी जरूरियात को इग्नोर करके वे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते है लेकिन आज स्कूलों में क्या हालत है। मैं अपने यहां की बात बताता हूं। हांसी तहसील में एक बास गांव है जिसमें हाई स्कूल है और बहुत अच्छा हाई स्कूल है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है और जिसमें आठ-दस स्टाफ क्वार्टर है। जब उस स्कूल के टीचर्ज ने फैसला किया कि हम स्ट्राइक पर जायेंगे और वह भी पीसफुल स्ट्राइक पर। सरकार को एक भी मिसाल नहीं मिलेगी कि कहीं पर टीचर्ज ने एक ईंट भी फेंकी हो या किसी प्रकार का वायलेंस किया हो तो मैं यह मानने के तैयार नहीं हूं कि टीचर्ज पीसफुल स्ट्राइक पर नहीं है। लेकिन बास गांव में जब टीचर्ज स्ट्राइक में शामिल हो गये तो बी0डी0ओ0 ने जाकर उन बच्चों और औरतों को जिनका कि स्ट्राइक से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके सामान को बाहर फिकवा दिया। क्या यही प्रजातन्त्र है। यह सरकार अपने को महात्मा गांधी के असूलों पर चलने वाली सरकार कहती है लेकिन महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह हे हथियार को हमको दिया उस पीसफुल सत्याग्रह को यह सरकार डंडे और लाठियों से दबाना चाहती हैं जो टीचर्ज डाक्टर पैदा करते हैं, इंजीनियर पैदा करते हैं, राष्ट्रपति पैदा करते है आज

यह सरकार उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है। इस तरह से तो हमारी भावना शिक्षा के बारे में बदल जायेगी। यह ठीक है कि सरकार के पास डंडा है, सरकार के पास ताकत है और वह टीचर्स की जायज मांग को इग्नोर कर दे, उनकी मांग को माने या न माने लेकिन इसका असर यह होगा कि आने वाले दस साल तक हमारी शिक्षा पनप नहीं सकेगी। सरकार की गलत पालिसी के कारण 1968 से हमारी शिक्षा को नुकसान पहुंच रहा है। जब ऐसी गंभीर स्थिति हमारी शिक्षा की हो तो इसके लिये अवश्य ही सोचना होगा। आज हिन्दुस्तान के अन्दर डेढ़ करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि हाइली क्वालीफाईड हैं और अनएम्पलायड हैं..

.....

**उपाध्यक्षा:** आप कितना टाईम और लेंगे?

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो अभी बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आपका जब तक हुक्म होगा बोलता रहूंगा आप जब कहेगी तो बैठ जाऊंगा।

**उपाध्यक्षा:** आप पांच मिनट और बोल लें अभी बहुत से मੈम्बरों ने बोलना है।

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बता रहा था कि सरकार के पास ताकत है, सरकार के लम्बे हाथ हैं लेकिन अगर वह टीचर्स से बात करके समस्या का कोई हल निकाल ले तो इससे उस पर कोई लाँछन नहीं आता। आज टीचर्स के कई



लीडर्ज भूख हड़ताल पर है और जिनकी बाबत कोई बुलेटिन तक नहीं निकलता कि उनका क्या हाल है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। भगवान न करे उनमें से कोई एक्सपायर हो गया तो स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। जो टीचर्ज इस अनएम्प्लायमेंट के जमाने में, रैली कर सकते है, अपनी नौकरी की परवाह न कर, अपने सिर पर कफन बांध कर दिल्ली जा सकते है, जब कि सरकार ने सारे रास्ते बन्द किये हुये है, और अगर किसी भी भूख हड़ताली को कुछ हो गया तो स्थिति ज्यादा खराब हो जायेगी। असल में यह जो सरकार से मैडल लने वाले हैं, यह जो बी0डी0ओ0 हैं, यह सरकार को गलत इनफरमेशन देते है और इसी वजह से सरकार को गलतफहमी रहती है। टीचर्ज को यह गलतफहमी थी कि हमारे इतने लोग है जिनकी ताकत से हम सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे और सरकार को यह गलतफहमी थी कि हमारे पास ताकत है, पुलिस है कोई भी स्कूल टीचर हिम्मत नहीं कर सकता कि वह दिल्ली जाकर हड़ताल में शामिल हो .....(घंटी)..... डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी तो मुझे चार-पांच बातें और कहनी है।

**उपाध्यक्षा:** आप कितना समय और लेंगे आपको बीस मिनट हो गये हैं और बहुत से मੈम्बरों ने बोलना है।

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब आप इंटरप्ट कर देती है तो मैं लाइन से हट जाता हूँ।

**उपाध्यक्षा:** आपको पांच मिनट और दिये जाते हैं।

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मुझे दस मिनट दीजिये। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक सद्भावना का वातावरण बनाया जये। बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, इसी चीज को ध्यान में रखकर टीचर्स की जो जायज मांगें हैं और जो 1957 से पेंडिंग है उन पर गौर किया जाये। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि टीचर्स की तो कोई मांग ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि टीचर्स की जो ग्रिवेंसिज हैं उनके बारे में मिनिस्टर का उनसे न मिलने के कारण, उनको एकामोडेट न करने के कारण गलतफहमी बढ़ गई हैं इस चीज से एक ऐसी भावना बन जायेगी कि लोग कहेंगे कि हमें तो इन टीचर्स से अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं और इस प्रकार की भावना से तालीम का बहुत नुकसान होगा। आज हो यह रहा है कि जिसको भी कम्बल ओढ़े देखे उसी को पकड़ लो, उसको अन्दर कर दो। चाहे वह कोई भी हो। जो पकड़े जाते हैं वह कहते हैं कि हम टीचर नहीं हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि यह तो अन्दर जाकर सफाई पेश करना कि वह कौन हैं। अब टीचर्स ने कुर्ते पहनना शुरू कर दिया है जिससे कि वह गिरफ्तारी से बच सकें।

इस तरह की भावना को बदलने के लिये सरकार को जरूर सोचना चाहिये और इस भावना को लम्बा नहीं खीचना चाहिये क्योंकि इससे अधिक नुकसान होने का डर है अगर कोई

टीचर इत्तफाक से गुजर गया तो मामला और भी अधिक गंभीर हो जायेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक इलैक्ट्रीसिटी का सवाल है, इस बारे में मुझे दो तीन सुझाव देने हैं। आपको पता ही है कि जै से पिछले दिनों बिजली की शार्टेज रही है और उस शार्टेज के वक्त में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है, वह ठीक नहीं रही। शार्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक हो सकता था लेकिन इसमें भी जिम्मवार अफसरों ने कोताही की है जिस की बिना पर कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा तो कभी एग्रीकल्चरिस्ट को ज्यादा बिजली दी गई। एग्रीकल्चरिस्ट को तो अगर सुबह को बिजली देने का टाईम था तो रात को मिली रात का टाईम था तो दिन को मिली। तो इस लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो अन-मीटर्ड केसिज है उन में बोर्ड की तरफ से पाबन्दी हैं। अक्वल तो बिजली मिलती ही नहीं और फिर किसानों से ट्यूबवैल्ज के लियेचाहे कोई 1 घंटा चलाये या 2 घंटा चलाये, उससे 6 घंटे का चार्ज किया जायेगा और नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी तक 6 घंटे का लिया है। अब मुझे पता चला है कि कोई 1घंटा चलाये या 2 घंटे चलाये अब उसे चार घंटे का देना पड़ेगा। कई बार तो कई-कई घंटे बिजली ही नहीं मिलतीण लेकिन उन गरीबों से फिर भी चार्ज कर लिया जाता है। इसके इलावा एक और बात है कि एक्चुअल सप्लाई की जो कन्जमशन होती है, वह तो 2घंटे की होती है पर उसको 6घंटे दिखाते हैं।। इससे किसानों को बड़ा

फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा दाम देने पड़ते हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक डोमैसटिक कन्वैशन्ज का सवाल है वहां पर भी बुरी हालत है, एक आदमी बिजली इस्तेमाल करे या न करे, कन्वैशजन मिलें या न मिलें, चाहे बिजली रोटी खाने के बाद आये, चाहे सुबह 4 बजे आये, उसे 2.75रूपये देने पड़ेंगे । पिछले दिनों, जबकि शार्टेज चली आ रही थी, उस वक्त आपको पता ही है कि देहातों में बिजली की क्या हालत थी । दो-तीन महीने रात को देहातों में कहीं बिजली नहीं मिली, अगर 15 मिनट आ गई तो सारा दिन चली गई । इसीलिये मैं यह समझता हूँ कि गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिये कि कन्जमशन चाहे थोड़ी हो और उन्हें दाम वही देने पड़ेंगे जोकि सरकार ने मुर्करर किये हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक जा-एंड-आर्डर का सवाल है, आपको पता ही है कि बड़ी सरकार की लड़ाई छोटी सरकार से हो रही है । अब मुसीबत यह है कि टीचर्ज का मसला है । उस में ला-एंड-आर्डर की सिचुएशन अब बिल्कुल ऐसी है कि बी0डी0ओज0 को, एस0डी0ओज0 और डाक्टर्ज को देखें, सभी उनके पीछे लगें हुये हैं । ला-एंड-आर्डर को मेनटेन करने के लिये सरकार को आराम से बैठकर टीचर्ज से बातचीत करनी चाहिए । आखिर वे भी तो सरकार के एम्प्लॉयज हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीच्यूशन्ज के तो वे एम्प्लायज नहीं हैं, इन्हीं के अंग हैं और इसी अंग का सुधार करने के लिये जिम्मेवारी से सरकार को

इसका हल निकालना चाहिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो यह लैन्ड सीलिंग बिल गरीबों के लिये बना है, उसके बारे में, मैं अपने रेवैन्यू मिनिस्टर साहब से बड़े अदब से कहूंगा वे बहुत समझदार है। हमें उम्मीद तो नहीं है कि 20 हजार कुनबों को जमीन मिल सकती है क्योंकि अभी तक आपके रूल्ज ही नहीं बने और जब तक रूल्ज नहीं बनेंगे तब तक जमीन कहीं की कहीं जा चुकी होगी। अगर थोड़ी बहुत है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके वे जल्दी से जल्दी रूल्ज बनवासें ताकि अगले बजट सेशन में यह पता चल सके कि कितनी जमीन लोगों को मिली है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक हास्पिटलज और डाक्टरज का सवाल है, कहीं पर हस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, कहीं हस्पतालों में दवाईयां नहीं है। जैसे कल एक सवाल सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार 150 रूपये आमदनी वाले आदमी को मैडिकल फ़ैसिलिटीज देने को तैयार है? तो उसके उत्तर में समाजवाद लाने वाली सरकार ने कहा कि अभी इसका कोई प्रोग्राम नहीं है और नहीं हम प्रोवाइड करसकते है। मेरी एक गुजारिश है कि जिन लोगों को दवाईयां नहीं मिलती, उनके बच्चे बिना इलाज के मर जाते है। गरीब आदमी कहां-कहां से मंहगी-मंहगी दवाईयां ला-ला कर अपने बच्चों को दे। इन लोगों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। (घंटी)..... डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और जरूरी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। (घंटी).....

**उपाध्यक्षा:** चौधरी अमर सिंह जी, आपका टाईम समाप्त हो चुका है।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** आन ए प्वायट आफ प्रोसीजर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी एक प्रार्थना है चाहे आप उसका जवाब कल को दे देना। यह जो मैम्बर्ज का इन्डीपैन्डेंट ग्रुप है, यह अपोजीशन का समझा जाये, कांग्रेस का न समझा जाये। यह 12 मैंबर तो अपनी ताकत से आये है। टिकट से सारी दुनिया आ जाती है। क्या यह पुलिटिकल आदमी नहीं है? 13 आदमियों को रिप्रेजेन्ट करता हूं। क्या हमें भी टाईम मिलेगा या नहीं? हम तो फाजिल्का की तरह न हरियाणा न पंजाब में बस यूं ही बीच में रह गये।

**उपाध्यक्षा:** चौधरी साहब आपको टाईम जरूर मिलेगा।

**श्री अमर सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायट आफ आर्डर है जैसा कि अभी दौलता साहब ने फरमाया कि मैं फाजिल्का तरह, न पंजाब में, न हरियाणा में, न कांग्रेस में। यहां जो मैंबर बैठा है, वह अपनी अपनी कांस्टीचुरेंसी को रिप्रेजेन्ट करता है लेकिन यहां पर नो मैन लैन्ड वाली बात नहीं है। अगर 11 आदमी लिखकर दे दे तो दौलता साहब वहां बैठेंगे जहां कि चौधरी हरिद्वारी लाल जी बैठते थे। अगर 11 आदमी नहीं है तो दौलता साहब वैसे ही कह रहे है। फिर ठीक ही किनारे पर बैठे है।

**उपाध्यक्षा:** यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नहीं है ।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** मैं तनख्वाह नहीं मांगूंगा, कार नहीं मांगूंगा, कोठी नहीं मांगूंगा, 11 का गुप बना कर दिखाऊंगा ।

**चौधरी मेहर चन्द:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे पांच मिनट तो इसी तरह खत्म हो गये ।

**उपाध्यक्षा:** नहीं आपका टाईम तभी शुरू होगा जब आप बोलना शुरू करेंगे ।

**चौधरी चांद राम:** मेरा प्वांयट आफ आर्डर है डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि हाउस के सामने थैंकस की मेन मोशन है । कुछ मेम्बरान ने कुछ अमेंडमेंटस दी हैं । कायदे के लिहाज से वह अमेंडमेंटस मूव होनीचाहिये और जो मैबर मुव करे, उसका नम्बर पहले आना चाहिये ।

**उपाध्यक्षा:** चौधरी साहब, जैसे कल स्पीकर साहब ने कह दिया था कि हमने यह समझ लिया है कि यह मूव हो गई है और जिन लोगों ने नोटिस दिया है उन्हें बोलने के लिये टाईम दिया जायेगा ।

**चौधरी चांद राम:** मोशन मूव करने का यह ढंग है कि मेन मोशन पहले मूव हो, सैकण्ड हो उसके बाद जिन लोगों ने मोशन पर अमेंडमेंटस दी, वह अमेंडमेंटस पहले पेश होनी चाहिये ।

वह कायदा पहले आप देख लें। अब मैंबर को जब आप टाईम ही न दें तो पेश कैसे होगी।

**उपाध्यक्षा:** चौधरी साहब, यह तो जब प्रस्ताव सैकण्ड हो गया था, उसके फोरन बाद यह पग उठाना चाहिये था। अब तो चार पांच मैंबर बोल चुके हैं।

**चौधरी चांद राम:** आप जब कुर्सी पर बैठी हुई हों, तो यह आपने ही देखना है अब अगर हम ज्यादा शोर करें तो लोग कहेंगे कि यह कभी बोलने पर करते है, कभी सीटों पर करते है, क्या करें, कहां गये प्रोजीसर? उनको तो आप बोला करो।

**श्री के० एन० गुलाटी:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, सबसे पहली मोशन मेरी है। मुझे टाईम दिया जाये।

**उपाध्यक्षा:** हां , देंगे।

**चौधरी मेहर चन्द(बडोपल):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर एड्रैस पर जो बहस चल रही है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो अच्छे काम किये है उनकी उस को दाद भी दूंगा और जो खामियां है उनकी तरफ सरकार की तवज्जों भी दिलाऊंगा लेकिन इस टापिक पर मैं कुछ देर बाद आऊंगा। कल मेरे एक मोहतरिम दोस्त ने जिनकी मैं कदर करता हूं हाउस के अन्दर यह फिकरा कहा कि '10 दिन और ठहरो'। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इस दिन के बाद क्या होगा?



वह कौन सा पहाड़ है जो टूटेगा। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे यह बात कह देना चाहता हूँ कि –

डराती क्या है रह रह कर ऐ बरके तपां हमको,

पेआं पे जिंदगी है दावते दर इम्तहां हमको,

वफा की राह में न डरना है, न दबना है

कि गीता ने बताया है यही राजे निहां हमको।

.....(प्रशंसा).....

हम बहस के लिये उनकी दावत कबूल करते हैं और बड़े शौक से कबूल करते हैं। कई इम्तहानों से गुजरे हैं यह एक और सही। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। मेरे एक और दोस्त हैं उनकी भी में कदर करता हूँ .....(विघन) उन्होंने कुछ और ही तरह की बात कही। ठीक है उनको बूढ़ों अखरते हैं। लेकिन यह बात नहीं कि यह सिर्फ मेरे ऊपर ही शायद होती है। चौधरी माडू सिंह और मित्तल साहब पर भी इकुयली आती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि बूढ़े लोग क्या इतने निकम्मे हो गये? उनको कुछ तो सोचना चाहिये, शायद वह भूल गये कि बूढ़े के पास एक्सपीरिऐंस होता है और वे अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं चौधरी साहब को टीचर्ज से इतना प्यार और हमसे इतनी नफरत। गजब खुदा का हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा लेकिन एक बात जरूर कहूंगा –

‘है नजर अपनी–अपनी, पसन्द अपनी–अपनी’

इनको बूढ़े पसन्द नहीं हैं .....(विघन).....

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज एक अजीब सी कफफियत है और वह यह है,

आदमी खुद काम, खुद परवर, खुद आरा है अभी,

सियासत के पर्दे में इनसान कितना आरा है अभी।

कुछ दिन पहले मेरे एक मोहतरिम दोस्त ने उसे मोहतरिम ही नहीं आलम फाजल भी कहूंगा एक खूब गलत ब्यानी की। उन्होंने फरमाया –

“Canals without water; complete electrification without electricity; hospitals without doctors and medicines; treasuries without cash.”

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं दाद देता हूँ उनको फिकरे क्यावन करने की। पब्लिक को गुमराह करना और गलत पत्लीसिटी करना गुनाह नहीं तो क्या हैं। मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा कानून है कि जिससे गलत ब्यानी करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अगर नहीं है तो कृपा करके ऐसा कानून कम से कम एम0एल0एल0 के लिये जरूर होना चाहिये। यह गलत बयानी उनके मुंह से सजती नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बगैर बिजली और बगैर पानी के फूड-ग्रेज और कौटन की पैदावार कैसे बढ़ गई, सिंचाई कैसे बढ़ गई? अनाज की पैदावार 26 लाख टन से बढ़ कर लगभग 50 लाख टन पर पहुँच गई है। क्या बगैर

नहरों के पानी और बगैर बिजली से हो गई? मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी स्टेटमेंट देना हो सोच समझ कर देना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि रूई की पैदावार तीन लाख गांठ से साढ़े चार लाख हो गई। यह भी बिजली और पानी की वजह से है। सिंचाई के बारे में मैं फिगरज को रिपीट नहीं करता लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि सिंचाई में लगभग 12 लाख एकड़ का इजाफा हुआ है। ये कहते हैं ट्यूबवैल को बिजली सप्लाई नहीं की जाती। अगर ट्यूबवैल को बिजली सप्लाई न की गई होती तो यह सब कैसे हो गया? क्या आसमान से उतरा है? ये लोग बिजली बोर्ड को दाद देने के बजाए उनको कंडेम करते हैं क्या तमाशा हैं? कभी यह सोचा है कि बरसात की कमी होते हुये भी बिजली की सप्लाई का लैवल कम नहीं होने दिया गया। हम दाद देते हैं बिजली बोर्ड के चेयरमैन और उसके कर्मचारियों को जिन्होंने इतनी दिक्कत के बावजूद भी हमको बिजली दी। कम्पलीट इलैक्ट्रीफिकेशन से पहले हमारी जो सप्लाई थी वह 40 लाख यूनिट डेली थी और आज वह सप्लाई लगभग 56 लाख यूनिट डेली है और वह भी उस हालत में है जबकि भाखड़ा से हमें 12-13 लाख यूनिट डेली कम मिल रही हैं नुक्ताचीनी कर देना बड़ी आसान बात है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने मोहतरिम दोस्त ये कहूंगा कि -

दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर,

अब नई सुबह व शाम पैदा कर।

मैं उनसे कहूंगा कि why to fritter away energies? That is a wrong way of working and criticising unnecessarily. डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजली के मुताल्लिक मैं एक बात ओर कहना चाहता हूं कि अगर हमें बदरपूर और कोटा से शिडयूल के मुताबिक सप्लाई मिल जाये तो वह कहीं 65 लाख यूनिट से भी ज्यादा होगी और आज जो बिजली की मांग है वह 65 लाख यूनिट के लगभग है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि बिजली बोर्ड ने कुदरत के साथ भी मुकाबला करते हुए इमदाद की हैं उनके अन्दर हुबलवतनी का मादा पाया गया हैं मैं कहता हूं कि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता अगर करता है तो सच्चाई से कोसे दूर है। यह भी कहा गया है कि हॉसपिटलज बगैर दवाई के है। मैं उनसे पुछना चाहता हूं कि मान लिया कहीं कोई सरकार ने गलत फिगर दी है। अगर गलत फिगर दी है तो आनैस्टली आपको सही फिगरज देकर चेलेंज कर देना चाहिये ताकि मिस स्टेटमेंट करें। अगर हस्पतालों की तरफ हरियाणा सरकार की तवज्जो नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा कि पांच रूपए फी कस से खर्चा बढ़ा कर 10 रूपये फी कस खर्चा हस्पतालों का कैसे हो गया? अगर यह बेबुनियाद चीज है, मैं सारी आपोजीशन को तो नहीं कहता क्योंकि सारे तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन चौधरी अमर सिंह ने अभी कहा था हस्पतालों में डाक्टरज नहीं हैं, दवाईयां नहीं है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो पांच रूपए फी कस खर्चा बढ़ गया है यह कैसे बढ़ गया? क्या उनके पास इस बात का जवाब है? We condemn ourselves by making

such false statements. इसके अलावा उन्होंने एक दो बातें और भी कहीं (विधान) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

**श्री अध्यक्ष:** आप अपनी बात कहें।

**चौधरी मेहर चन्द:** उनसे कहें कि वह मुझे इन्द्रुप्ट न करें वना I will pay in the me coin, with your permission, of course. When I join issue, join issue boldly and not like a coward.

**श्री अध्यक्ष:** आप अपनी स्पीच जारी रखें।

**चौधरी मेहर चन्द:** ठीक हैं, स्पीकर साहब, मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैडीसन्ज, बिजली और पानी की बात तो आ गई हैं चौथी बात उन्होंने यह कही कि जो ट्रेजरीज है उन में रूपया पैसा नहीं है। मे। कहता हूँ कि अगर ट्रेजरीज में रूपया पैसा न होता तो यह विकास के काम कैसे जारी रहते, सड़कें भी बन रही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि सड़कें न बनीं हो, वे अब भी बन रही है, वाटरवर्क्स का काम भी हो रहा है, हस्पतालों का भी काम हो रहा है और हर शोअबा में काम हो रहा है। मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सब कुछ बगैर रूपये पैसे के ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये उन की सब बेबुनियाद बातें हैं, उन्हें ऐसी बातें कहनेसे गुरेज करना चाहिए। टीचर्ज की जो बात है उस पर कुछ कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार की बाबत। वह यह है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो सब को उनकी तारीफ करनी

चाहिए न कि उनकी कंडैमनेशन करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने क्या किया इस के बारे में चार मिसरों से एक बात कहना चाहता हूं। यह मेरे भाई जिन्होंने नुक्ताचीनी की है वे जरा गौर से सुन लें,

कांटो को फूल सहरा को बाग कर रही है,  
वतन की ख़जां को फसले बहार कर रही है,  
खाके वतन का ऊंचा वह नाम कर रही है,  
सानी न होगा जिसका वह काम कर रही है।

**चौधरी शिव राम वर्मा:** आखिरी मिसरा जो आपने कहा वह ठीक है।

**चौधरी मेहर चन्द:** यह है हमारी कांग्रेस सरकार, जन संघ वाली क्या बात कर रहे हो? (सरकारी बेंचो की और से तालियां)

स्पीकर साहब, अब मैं एक बात और कहूं, यह जो मसनूई सन्त हैं, फर्जी लीडर है और फर्जी मास्टर है यह सारे बड़े भारी ब्लौटस है हरियाणा के ऊपर। मैं तो जनात को एक ही बात कहूंगा कि –

जाग उठो जाग उठो अहले वतन,

अब दौरे मसती कहां?

नई अजीयत नया इम्तहां है ।

जागो जगन फिर उभर आए

खतरे में आशियां है ॥ (विघ्न)

यह तो शायर ने कहा है, मैं तो शेर सुना रहा हूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। स्पीकर साहब, आज कल आपोजीशन ने, मैं सब को नहीं कहता, लेकिन जिन का काम महज गर्वनमेंट की मुखालफित ही करना है, उन्होंने तीन चार बातों पर खूब जोर दिया हुआ है और वह क्या है, एक तो जनता के दिलों स्याह करने पर, वतन को कमजोर करने पर, कौम को मौहताज करने पर, नौजवानों को गद्दार करने पर और बदइन्तजामी फैलाने पर। इन चीजों का ठेका खूब लिया है। मैं इन से पूछता हूं कि कोई भला काम भी है जो आप करते है। स्पीकर साहब—

ईसा तो सैंकडों हैं,

मर्ज की दवा नहीं ।

अरे मर्ज की भी दवा करो, ईसा तो आप बहुत हैं ।

अब मैं एक अहम मसले की तरफ आता हूं जिस की बाबत इन्होंने हाऊस में शोर मचा रखा है। चौधरी दल सिंह ने तो ऐसे कर रखा है जैसे कुरता ही फाड़ दिया जाये। वह जामा से बाहर निकल रहे है। अगर उन्होंने जामा से बाहर निकलना है तो

वह बाहर जा कर निकल सकते है हाउस के अन्दर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। आपोजीशन के चन्द साथियों ने मास्टर्स के प्रति बहुत हमदर्दी का इजहार किया। चौधरी दल सिंह ने तो उस्तादों की कदर करने को भी कहा है, ख्याल बड़ा नेक है उनकी इस बात को मानता हूं। इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूं कि उस्तादों की कदर करनी चाहिए लेकिन किन उस्तादों की? क्या उन उस्तादों की जो इनडिसिपलिन पैदा करें, क्या उनकी जो बच्चों को न पढ़ायें और न पढ़ने दें। क्या उन उस्तादों की जो बच्चों को यह कहें कि माँ और बाप का कहना मत मानों, क्या उनकी जो पौलिटिकस में डैवल करते है, क्या उनसे हमदर्दी करनी चाहिए जो गदर फैला रहे है? आप अपने सीने पर हाथ रख कर देखें, अपने दिलों को टटोल कर देखें कि जो आप नुक्ताचीनी कर रहे है वह सही है या कि कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है जो स्टैंड ले रही है वह सही है। सिर्फ एक ही नुक्ता नजर से न देखें कि कांग्रेस पार्टी अगर एक बात करती है तो हमने जरूर उल्टी बात करनी है। अगर आप का यही नजरिया है तो यह गलत है। हम को यह देखना चाहिए कि चीज की सदाकत क्या है। कौन कहता है कि उस्तादों की इज्जत नहीं करना चाहिए, क्या चीफ मिनिस्टर हरियाणा यह कहते है— हरगिज नहीं, क्या कांग्रेस के और मिनिस्टर यह कहते है— हरगिज नहीं कहते, क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कहती है—बिल्कुल नहीं कहती। इसलिए अगर ऐसा प्रोपैगण्डा फैलाया जाता है तो यह गलत प्रोपैगण्डा है। मैं तो यह कहता हूं कि जिन टीचर्स की बात की जा रही है ते हमदर्दी के



बिल्कुल हकदार नहीं है, लीनएंसी की तो बात ही छोड़िये। मैं तो अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस किस्म की बदअमनी फैलाएं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो आदमी इस किस्म की बदअमनी प्रदेश में फैलाये उनको हम गुरु कैसे कहें? मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये और सख्त और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर अब सरकार झुकती है तो मैं इस पालिसी को ठीक नहीं समझूंगा क्योंकि जिसने हरियाणा में बदअमनी फैलाई है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिये और सजा भी वह मिलनी चाहिये जो इबरतनाक हो। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये और माननी चाहिए जिससे हरियाणा स्टेट पर और हरियाणा की जनता पर फायनैशल बर्डन पड़े। मैं इस बात के सौ फीसदी खिलाफ हूं चाहे मैं अगली दफा रिटर्न हूं या न होऊं, चाहे जिन्दा रहूं या न रहूं, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि हरियाणा पर कोई ऐसी बात करके फायनैशल बर्डन डाला जाये। मैं कहता हूं कि स्टेट का विकास कैसे होगा यह सोचने वाली बात है दूसरी कोई नहीं। हम तो यह चाहते हैं कि हरियाणा तरक्की के मैदान में ऊंचा उठे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की दाद देता हूं कि उन्होंने हरियाणा का नाम सारे देश में रोशन किया है। ये कहेंगे कि आप फिर उसी तरफ आ जाते हैं लेकिन जो हकीकत है मैं उसे बताने से नहीं रूक सकता, हट नहीं सकता। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और वह मेरी जाति राय की बात है। मैं

नहीं जानता कि सरकार की क्या पालिसी है और वह क्या करना ठीक समझती है। वह बात यह है और अगर सरकार इस बारे में सोच ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि यह जो उसकी पोस्टिंग की पालिसी है उसे रिवाइज कर दे। एकदम नहीं रफता रफता कर दे। इनके दवाब में आकर और इनकी धमकियों में आ कर नहीं। तो अगर सरकार इस बारे में कुछ सोच ले और इसमें कुछ तबदीली कर दी जाये तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह मेरा अपना जाति ख्याल है मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि उसका क्या ख्याल है और वह क्या करना चाहती है। मेरा तो यह सुझाव है आगे सरकार बेहतर जानती हे कि क्या करना मुनासिब हैं इसके अलावा मैं अर्ज करता हूं कि पहले दो किस्म के मसनूई आदमी पाये जाते थे। एक फर्जी सन्त और दूसरे फर्जी लीडर पाये जाते थे लेकिन अब एक और जमात इस जमात में जमां हो गई है और वह हो गई है फर्जी मास्टर। अब यह तीन क्लास बन गये है और अब तीनों गुटबन्दी की है। इन्होंने कहा हरियाणा को बरबाद कर दो, हरियाणा में बदअमनी फैला दो लेकिन उनको शायद इस बात का पता नहीं कि यहां पर चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल है इसलिये सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी। उनको शायद इस बात का पता नहीं, भूल गये हैं, वरना यह हरकत न करते। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो बदअमनी फैलानेवाली अब बात है क्या यह देश के साथ गद्दारी नहीं है और क्या है और इसे और क्या कहा जाये? मैं तो स्पीकार साहब आपकी मारफत

हरियाणा की जनता को इस मसनूयात और फर्जियात के बारे में इतना ही कहूंगा और वह शेर की शकल में है---

**श्री अध्यक्ष:** यह आपका आखिरी शेर ही होगा टाईम हो गया है।

**चौधरी मेहर चन्द:** स्पीकर साहब, आपकी मर्जी की बात है मैं तो जब आप कहेंगे बैठ जाऊंगा, मैं तो आपके हुक्म का पाबन्द हूँ और सर्विस में मैंने यही बात सीखी है कि डिस्प्लिन से काम करना है लेकिन मैं आप से यह अर्ज करता हूँ कि मुझे जरा टाईम और दे दें, मैंने अभी तो कुछ कहा ही नहीं है। तो शेर यूँ है ---

रंगे चमन दिखायेगा सीनाये दागदार था?

करेगा वो वतन को पायेदार क्या?

न जिस का दीन है न ईमान है,

वहां हुबवेवतन कहां, अपना ही ध्यान है।

क्या आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वह वतन को मजबुत कर सकेंगे जिसका सीना दागदार है और न जिसका दीन है और न ईमान है? ऐसे आदमी में हुबलवत्नी कहां, उसे तो अपना ही ध्यान है। (विधन) ऐसे आदमी जिनके ऐसे ख्यालात हों वे वतन में बहार नहीं ला सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में भी जो कोई उड़ता है आपोजीशन वालों की तरफ से वह कुछ न कुछ कहता

है। मैं पूछता हूँ कि वे जलते क्यों हैं? इस बारे में भी मैं आपको एक शेर सुना दूँ कि वे क्यों जलते हैं और वह यह है –

महफले दुनिया में वह एक ऐसी नगमा साज है,

कि जिसकी खातिर सारा आल्म गोशवर आवाज है।

गुलशाने भारत वह बंगला की चमनआरा है वह,

बेज़बानों की ज़बान दिल का सहारा है वह।

जो भी उठता है चाहे जनसंघ का हो या ओर ए0बी0सी0 हो व कुछ न कुछ कहता। उनके खिलाफ और मैं समझता हूँ कि वे अपने दिल की जलन को ऐसा करके दिखाते हैं हर काम करने वाले से जलन होती ही है और इनको जो जलन है वह यह कि यह खुद कुछ नहीं कर सकते दूसरों को अच्छे काम करते देख नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा के विकास के लिये जो-जो काम किये हैं उनको सारा हिन्दुस्तान तो देख रहा है लेकिन इनको नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री जी से इनको क्यों जलन है उस बारे में भी एक शेर कह देता हूँ और वह यह है—

दुश्मनों से भी वफायें दोस्ती लेता है वह,

चाक सीने में भी हो जाये तो सी लेता है वह।

कांटों में रह कर भी फूल उस ने वह खिलाये है,

कि अहले वतन उस की गलअफशानियों पर मुस्कुराये है।

स्पीकर साहब, अब मैं राज्यपाल साहब के एड्रैस की तरफ आता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि (विधान)

**चौधरी शिव राम वर्मा:** आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैं पूछता हूँ कि यह इतनी देर क्या करते रहे जो अब राज्यपाल साहब के एड्रैस की तरफ आये है? यह अब पहले क्या टाईम खराब करते रहे है जो अब इधर आये है (हंसी)।

**चौधरी मेहर चन्द:** स्पीकर साहब, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि मैंने टाईम खराब नहीं किया है और इनकी गलत बातों का परदा फाश करता रहा हूँ। इसलिये अब इस एड्रैस की तरफ आया हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय के एड्रैस का समर्थन क्यों करता हूँ और वह मैं इसलिये करता हूँ कि इस एड्रैस में हकीकत बयान की गई है और साबित किया गया है कि हरियाणा तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ गामजन है। बावजूद इन एजीटेशनन्ज के हरियाणा सरकार की सारी तवज्जुह विकास के कामों की तरफ है इसके लिये यह गवर्नमेंट एग्रेसिएशन की हकदार है खास तौर पर इन अदारों में और इन शोअबों में –

- (1) Opening of fair price shops for providing foodgrains to consumers and at reasonable price;

- (2) Distribution of controlled cloth through fair price shops;
- (3) paying increased attention in the matter of providing medical facilities;
- (4) speedy increase in agricultural production;
- (5) Expansion in minor irrigation, canal irrigation and irrigation through tube-well corporation;
- (6) Significant progress in dairy development and for providing loans to farmers and landless labour for purchasing good quality milch cattle;
- (7) Taking steps to increase power generation in the State so as to enhance agricultural production and accelerate industrial development;
- (8) Significant progress in industrial development in the towns;
- (9) Continuing work on construction of new roads despite paucity of funds;
- (10) Eradicating beggary and setting up an institution for that purpose.

कुछ अदारे ऐसे भी है जिनकी तरफ गवर्नमेंट ने काफी ध्यान नहीं दिया है। स्पीकर साहब, अब मैं आपकी मारफत गवर्नमेंट से विनती करूंगा कि इन अदारों की तरफ खास ध्यान दें। मेरे भाई श्री अमर

सिंह ने रूरल इंडस्ट्रलाईजेशन के बारे में एक बात कही। लेकिन वे भूल न जाएं कि यह आईडिया भी बंदे से ही लिया है। (हंसी)। दूसरी चीज एम्पलायमेंट के बारे में है Assuming responsibility for providing employment to every able bodied person in the field or factory. एम्पलायमेंट प्रोवाईड हो रही है लेकिन जब तक गर्वनमेंट सही मायनों में रिस्पांसिबिलिटी अज्यूम न करे कि किसी भी एबल बौडीड परसन को बेकार नहीं रखा जाएगा तब तक अन-एम्पलायमेंट की समस्या दूर नहीं होगी। जब तक इन नौजवानों को खेती-बाड़ी के काम में नहीं लगाया जाएगा, वर्कशाप में नहीं लगाया जायेगा, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा तब तक अन-एम्पलायमेंट दूर नहीं होगी। तीसरी चीज हाउसिंग प्रोग्राम इन रूरल एरियाज में देने की है, वैसे तो इसके बारे में गर्वनर ऐड्रैस में बहुत कुछ दिया है। मेरे खयाल में हाउसिंग प्रोग्राम के मुताल्लिक फरीदाबाद में हद ही कर दी है। (घंटी) स्पीकर साहब, आपने घंटी बजा दी है, मुझे दो मिनट और दे दें। अभी मैंने यह भी बताना है कि गर्वनर ऐड्रैस में कमी किस बात की है। खैर गर्वनर ऐड्र के बारे में आपने काफी कुछ सुन लिया है इसलिए ये कमियां मैं नहीं बताता लेकिन इतना जरूर दरख्वासत करूंगा कि रूरल एरियाज में हाउसिंग प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। इसके अलावा :-

Constructing a lined channel to carry to Haryana through Punjab territory the extra water to be made available to Haryana as its share of Ravi-Beas waters.

I think, this should receive top priority. Every thing else may be left out. But this thing should receive the top priority. इसके अलावा:— Setting up a few small scale industries in Hissar district through the Harijan Kalyan Nigam for providing employment to Harijan families. इसमें यह नहीं होना चाहिए कि श्याम चन्द जी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सिर्फ रोहतक की तरफ ले जाएं, हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ भी ध्यान दे। इसे बाद Opening of a training centre for imparting training to non-Harijan boys particularly for rural areas fro competing in various competitive examinations. यह नहीं क चौधरी चांद राम जी कहते है कि हरिजनों के लिए ही सब कुछ हो। आखिर हम भी तो इस दुनिया में बैठे हैं हमारे बच्चे भी रूरल एरियाज के है और बैकवर्ड है। उनके लिए भी ऐसी ही सुविधाएं होनी चाहिएं जैसे हरिजन लड़कों के लिए होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि वे भी इस कम्पीटीशन में दाखिल हो जाये। अच्छा जी मेम्बर साहिबान की एक बात मैं आखिर में पूरी कर दूं। मैं हाउस को एक बात कहना चाहूंगा कि आउस की भावना क्या होनी चाहिए? स्पीकर साहब, माफ करें, आपकी समझ में यह शेर नहीं आयेगा क्योंकि आपने एक दिन मुझे कहा था। शेर इस तरह है :—

तंगिए दिल गर न हो तो तंगिए दामन नहीं,

साकिने गुलशन नहीं जो मौसमें गुलशन नहीं।

असल इन्सान तो वह है जो अपने वतन पर अहसान करता हो—



न हो जिस चमन में बहार कभी आई,

है उससे खुशतर किसी उस सहारा की तन्हाई।(तालियां)

इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता(बेरी):** जनाबे स्पीकर साहब, 14 साल हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद मेरी एक आदत पड़ गई कि अगर हाई कोर्ट में कोई वकील आर्गमेंट कर रहा हो तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देता। जब वह बोल रहा हो तो कोई उसे डिस्टर्ब न करे। इसीलिये न मैं किसी की स्पीच के दौरान बोला और न कोई मेरी स्पीच के बीच में बोले। आप टाईम बता दें, मैं उसी में, रेगुलेट करने की कोशिश करूंगा। स्पीकर साहब, कई एक मैटर इतने कुशल है कि उनका जवाब दना पड़ेगा। सबसे पहली बात एड्रैस के बारे में हैं। यह एड्रैस जहां तक भी जाता है उसके मुताबिक यह बहुत अच्छा एड्रैस है। लेकिन मुझे ख्याल है कि इसमें कुछ न कुछ ओमिशन है। ओमिशन पोलिटिकल इशू पर है जहां पर लोगों का ध्यान है। गवर्नर एड्रैस के मायने होते हैं कि जो इम्पार्टेंट इक्विसादी या तरक्कियाती मसले अगले साल में होने होते हैं उन के बारे में इस एड्रैस के जरिए, हाउस को कन्फिडेंस में लिया जाये। अगर हाउस टूटा हुआ हो और सी0एम0 एग्जैक्टिव पावर हो और हाउस को इग्नोर करना चाहे तो एक ही तरीका है और वह है कि जैसे पार्जियामेंट में कांग्रेस एम0पीज0 या दूसरे एम0पीज0 डट जाते हैं। हमने प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी

और स्वर्गीय पंडित जी की बाहर कोई इम्पोर्टेंट स्पीच नहीं देखी। यह कभी नहीं होता था कि डिस्ट्रिक्ट टूट जाए और उस एम0एल0ए0 को यह पता भी न लगे कि तेरे गांव किधर गये। इसमें दो तीन पोलिटिकल इशु शामिल है। एक इशू चण्डीगढ़ का है। क्या चण्डीगढ़ के मामले में शाह कमीशन को बिल्कुल छोड़ दिया गया? क्या इन्दिरा अवार्ड इम्प्लीमेंट होगा, अगर नहीं होगा तो इस पर हमारी सरकार क्या करना चाहती है? एक इशू तो यह है और दूसरा मेरा एक सुझाव है। अफवाहें तरह-तरह की फैली हुई है, पता नहीं लगता कई चीजें अचानक हो जाती है। सुना है हाई कोर्ट का एक बेंच कहीं जा रहा है। A Bench will be a forerunner for the High Court and the High Court will be a forerunner for the capital. कहीं ऐसी कोई बात न हो जाए कि जब हम सुबह उठें तो पता लगे कि हम वहां पहुंच गये है। इस मामले में हाउस को कान्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। इस के बारे में मेरा सुझाव है कि जब तक चण्डीगढ़ हमें नहीं मिलता, शाह कमीशन की रिपोर्ट पर अमल नहीं होता तब तक कहीं न जाएं। मैं तो उस रैजोल्यूशन पर कायम हूँ जो हमने यूनानिमसली पास किया था और सी0एम0 साहब भी उस वक्त थे। जुडीशयरी ने तो यह तसलीम कर लिया कि चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और अगर चण्डीगढ़ न मिले तो इंदिरा अवार्ड मिले। अगर दोनों ही न हमलें तो सी0एम0 साहब आज के दिन पावरफुल हैं ही। मैं यह कहते हुए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता कि इंडिया में जो पावर आज बंसी लाल के हाथ में है वह जस्टिफाइड है। मुझे इस बात का

फख है कि इतनी जबरदस्त पोलिटिकल पावर आज इनके हाथ में है। अम सब इनके साथ है। अगर आन्ध्र वाले लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं और अगर दोनों में से कोई बात नहीं हुई तो हम जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यह हमारी पहली पोलिटिकल बात है।

दूसरी पोलिटिकल बात यह है जो कल चौधरी हरद्वारी लाल जी ने कहा था कि जो मेरे पीछे मैम्बर बैठे थे वे कहां गए। (हंसी) स्पीकर साहब, एक इंडीपेंडेंट मैम्बर के लिए बोलना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं वह बात कहूं जो बंसी लाल जी को अच्छी लगे तो कुछ भाई और अखबार वाले जिन्हें बंसी लाल जी से खास प्रेम है, कहेंगे कि कुछ ब्राईब हो गया है, कुछ मिल गया है। अगर मैं इन्हे कंडैम करूं तो दूसरी बात हो जाती है। जहां तक कंडैम करने वाली बात है, मैं कंडैम करता हूं और करूंगा। लेकिन इन्ही बंसी लाल जी ने जो सबसे बड़ी सर्विस की है वह कभी नहीं की जा सकती और वह है छः मैम्बरों का आना और जाना। 1972 में जब इलैक्शन हुआ उसका आपको याद होगा। एक बात मैं अलग से अर्ज कर दूं कि कांग्रेस में जो भाई टक्साली मैम्बर है, तो एक बात सीख लें कि अपोजीशन क्या होती है जिन मैम्बरों को वजीरियां नहीं मिली वे नाराज बैठे होंगे। कांग्रेसी-पावर की अपोजीशन यानी रूलिंग पावर की अपोजीशन के मायने ये है जो तीन चीजों के खिलाफ हो— डैमोक्रेसी, सोशलिज्म और सैकुलरिज्म। ये तीन स्तून हैं, जो कांग्रेस की आइडियोलोजी को

लेकर इलैकशन लड़ते है जैसे सी०पी०आई० और कांग्रेस-ओ, इनसे आज हकूमत को रस्मी स्पोर्ट है। जो आदमी इन सिद्धातों के मुखलिफ है वह अपोजीशन है। जो आदमी इन तीन चीजों में यकीन रखता है उसको चाहे यहां सीट अलाट कर दो, चाहे वहां अलाट कर दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंटर में जो गवर्नमेंट हैं और जो उसका हिमायती है, उसका साथी है वह उसका अपोजीशन नहीं है। 1972 में, स्पीकर साहब, हरियाणा के साथ एक अजीब बात हुई। जब मैंने रिजल्ट का दूसरे दिन अखबार पढ़ा तो कम से कम मुझे अपनी फतह पर खुशी नहीं हुई थी। हमारे साथ उस समय बड़ी अजीब बात हुई थी। हिन्दुस्तान भर में ग्रांड अलायंस-जनसंघ, स्वतन्त्र और अकाली पार्टीज और हिन्दू महा सभा वगैरा जो फिरका परस्त पार्टीज है, इनकी तमाम हिन्दुस्तान में बुरी तरह डिफीट होती चली गई लेकिन कांग्रेस ओ को इस हाउस में ऐसी रिकगनाईजड अपोजीशन हासिल हुई थी जो श्री मुरार जी देसाई को भी गुजरात में हासिल नहीं हुई थी। हम सब जो साशलिस्ट ख्यालात के आदमी थे वे सबसे ज्यादा परटवर्ड थे। इंडीपेंडेंट उम्मीदवार का मजाक किया जाता है। हम कांग्रेस ओ को यानी ग्रांड अलायंस को डिमोरेलाईज करना चाहते थे। कांग्रेस-ओ उन मेम्बरों को डिमोरेलाईज करना चाहते थे जो बिके नहीं। आज जो तरह तरह की अस्पार्शन की बातें की जाती है वे ठीक नहीं हैं। हमने तो कांग्रेस-ओ की, ग्रांड अलायंस की रूज्जतपसन्दी की कमर तोड़ दी थी। पिछले सैशन में हमने इनको बता दिया था लेकिन अब आपने विदड्रा कर लिया है, ये बैठे हैं,

(चौधरी हरद्वारी लाल की तरफ इशारा करते हुए) कहां भाग गए। अब रूज्जतपसन्दी की कमर तोड़ने के बाद, ग्रांड अलायंस को डिफीट देने के बाद पोलिटिकल तरीके से सोने वाले आदमियों को मालूम होना चाहिये कि जो सर्विस और कोई नहीं हो सकती। सोशलिज्म, डैमोक्रेसी तो कोई है नहीं। ठीक है, मेरे पीछे आने की तो हिम्मत न हो लेकिन मैं आपसे एक अर्ज कर दूँ कि जो इंडिपेंडेंट आदमी कांग्रेस-ओ की टिकट पर कामयाब नहीं हुए थे वे सारे तकरीबन-तकरीबन इंदिरा भगत है, कांग्रेस भगत हैं। बंसी लाल को हमारे चेहरे से चिढ़ हो और हमें उनके चेहरे से चिढ़ हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है, जिनके आइडियाज एक हैं, वे मेरे पीछे तो नहीं लेकिन इंदिरा के पीछे हैं, बंसी लाल के पीछे हैं और मैं भी उनके पीछे हूँ। (तालियां)

इकसे इलावा दूसरा जो पोलिटिकल इशू है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस के वे दो स्पीकर जो अपनी स्पीच दे चुके हैं, उन्होंने इस इशू का जिक्र नहीं किया। स्पीकर साहब, जब मुझे किसी मैम्बर की कांस्टीच्युएंसी का पता न हो तभी मैं आनरेबल मैम्बर का नाम लोता हूँ। चौधरी स्वरूप सिंह की कांस्टीच्युएंसी के नाम का मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आनरेबल मैम्बर चौधरी स्वरूप सिंह ही कह देता हूँ। उन्होंने कहा कि 1967 का साल बेकार चला गया क्योंकि यह साल डिवैल्पमेंट करने के काम नहीं आया। स्पीकर साहब, हम घमंड से कहते हैं कि आज यह डायनेमिक लीडरशिप जो बंसी लाल जी की

हमें मिली है, इसके लिए 1967 में हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी करके ली है। हमने एक ऐसे आदमी को आउस्ट किया था जिसको जात-पात के नाम पर कांग्रेस की टिकट मिलती थी और उनके खिलाफ कैंडीडेट खड़े करते थे। हमने बगावत की थी लेकिन डिफैक्शन नहीं। हम डिफैक्टर नहीं थे। हम में से डिफैक्टर सिर्फ तीन थे। आज आंध्र प्रदेश में कांग्रेस टिकट पर 14 एम.पी.ज. बगावत करने में कामयाब हुए और यह पोलिटिकल डिफैक्शन है। अब तो डिफाईन हो चुका है कि डिफैक्शन क्या है ? जो बिल आ रहा है उसमें डिफाईन हो चुका है। उस डेफिनीशन में यह है कि डिफैक्टर वह नहीं है जो किसी प्रिंसिपल या असूल की बिना पर हो। डिफैक्शन वो है जो सिर्फ वजीरी का लालच या ओहदा लेने के लालच से एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करे। हमने नन्दा जी के मकान पर, शायद आप भी वहां मौजूद होंगे वैसे तो बहुत लोग मौजूद होंगे, मैंने उठकर नन्दा जी को कह दिया था कि हम उस लीडर को बिलकुल एक्सैप्ट नहीं करेंगे जो कांग्रेस के खिलाफ ही कैंडीडेट खड़ा करता हो। हम बगावत करेंगे, नहीं तो आप इसको रिमूव कीजिए। हमने बगावत की। 11-12 आदमियों ने बगावत की, डिफैक्शन नहीं की। डिफैक्शन सिर्फ तीन आदमियों ने की थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन चौधरी हरद्वारी लाल जा?ी का नाम जरूर लूंगा। उन्होंने अपना डिफैक्शन धो लिया था क्योंकि इलैक्शन लड़ लिया था। दो और मैम्बर थे जो वजारत बनने के बाद सिर्फ वजीरी के लालच में आये थे ओर वो दोनों उधर बैठे हैं। बार बार हमारी तरफ उंगली

न करें क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। इसके अलावा जिन आदमियों ने गवर्नर को 14 बार लिख कर दिया है, जिन्होंने पहली शाम को कुछ दस्तखत कर दिए और दूसरे दिन कुछ और दस्तखत कर दिए, यह ठीक नहीं है। एक आदमी पंडित भगवत दयाल से कहने लगा कि पंडित जी, क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है कि एक आदमी दस्तखत भी कर दे और 'बेरा भी न पाट्टे'। वे सब लोग उधर बैठे हैं जिन्होंने डिफैक्शन की है। अगर डिफैक्शन की बात चले तो आप परली तरफ उंगली किया करें, हमारी तरफ न किया करें। यह बात डिफैक्शन की रही।

स्पीकर साहब, जो ज्यादा पोलिटिकल इशू है वह मेरे लिए अनप्लैजेंट हैं। मैं इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं करता कि मुझे बंसी लाल जी की परसनैलिटी की बहुत सारी हरकतें बिल्कुल पसन्द नहीं है। मुझे उनी एरोगैस बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उनका हाउस को नथिंग तक रिड्यूस कर देना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे उनका कैबिनेट के साथ— कैबिनेट सिस्टम मीन्ज सी0एम0 नम्बर वन नान—इक्वल— मुझे पसंद नहीं। लेकिन जनसंघ वाले मेम्बर जो मुखालिफत पोलिटिकल पार्टी है, बड़े सिंसीयर आदमी है। मुखालिफत करो लेकिन मुखालिफत की तरह। पोलिटिकल लड़ाई लड़ो। तुम हटा सकते हो कांग्रेस को और कांग्रेस वाले हटा सकते है अपने लीडर को लेकिन हरियाणा को बदनाम न करो। मैं अभी खड़गबासला गया था क्योंकि मेरे लड़के ने वहां आर्मी में पास आऊट किया। वहां मुझे जितने

जनरलज मिले, जितने और लोग मिले, जिनका पोलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं, Everybody congratulated me, Oh, you came from Haryana जहां इतनी डिवैल्पमेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं। डिवैल्पमेंट का क्रेडिट जाता है उन आदमियों को जिन्होंने हरियाणा बनवाया हैं वे मेरे जैसे सियाने आदमी थे जिन्होंने सात साल पहले पार्लियामेंट में बात की थी लेकिन उससे ज्यादा क्रेडिट बंसी लाल को जाता है। जो आदमी इसमें ऊंच नीच करता है वह उसकी अपनी मर्जी है। आपको पोलिटिकल हक है बंसी लाल से लड़ने का। आप बड़ी खुशी से लड़े लेकिन यह जो करप्शन वाली बात है, यह जो राष्ट्रपति को मैमोरैन्डम देना है यह बड़ा घटिया किस्म का चीप पोलिटिकल वैपन हो गया है। इस घटिया पोलिटिकल वैपन से बहुत बड़ा आदमी, सरदार प्रताप सिंह कैरों, बरबाद हुआ। सरदार प्रताप सिंह कैरों को जब लोग पोलिटिकल डिफिट न दे सके तो कुछेक कागजी लोग मैमोरैन्डम लेकर फिरते रहे। हाई कमांड के भी कुछ आदमी उसे खत्म करना चाहते थे, इसलिये वह बेचारा सड़क पर पड़ा पाया गया। पंजाब की धरती को वह पाप हमेशा है। स्पीकर साहब, आपके जो प्रैडीसेंसर थे उन्होंने भी कहा था कि हरियाणा में जहां कस्सी मारो वहां करप्शन है। मैं दावे से कहता हूं कि जो आदमी हरियाणा में जनरल करप्शन की बात करते हैं या जो आदमी यह कहते हैं कि बंसी लाल ने अपनी जेब गर्म कर ली। वे पोलिटिकल लोग हैं, जो पोलिटिकल तौर पर कांग्रेस को, बंसी लाल को डिफिट न दे सके। वे इस छोटे हथियार पर आ गए हैं जिसे करैक्टर असेसिनेशन



कहते हैं। मैं वकील हूँ। मुझे आदत है कोर्ट करने की। मेरे पास जो कटिंग है वह एक ऐसे जरनेलिस्ट की है जो प्रो-बंसी लाल नहीं है बल्कि बंसी लाल जी से उसे बहुत शिकायत है। यह बात मुझे पर्सनली मालूम है। यह कटिंग दिल्ली के एक बड़े जिम्मेवार अखबार की है। मुझे बड़ी खुशी हुई यह पढ़ कर कि जिस तरह मैं सोचता हूँ उसी तरह इसने सोचा है। जब हरियाणा और पंजाब को बने पांच साल पूरे हो गए तब इन्होंने हरियाणा और पंजाब दोनों की अचीवमेंट्स को कम्पेयर किया है। उन अचीवमेंट्स में बंसी लाल की अचीवमेंट्स उन्होंने पहले खूब गिनाई है। वे वहां हैं जिनको मैं आमतौर पर सोचा करता हूँ। फिर बाद में क्विटिसाईज भी किया है। वे भी तकरीबन मेरे ही आर्गुमेंट्स हैं। वे पोलिटिकल इश्यू पर लिखते हैं –

“Mr. Bansi Lal, Chief Minister was not wrong when during the recent Assembly Session he said that having been routed in open confrontation the Opposition has started hitting below the belt. It was now playing the game of character assassination to get rid of the Chief Minister. The scene is reminiscent of the days of Sardar Partap Singh Kairon whose adversaries failed in every other way to oust him. The Opposition has now presented yet another Memorandum to the President alleging corruption in the State Government.”

मैं भी अर्ज किए देता हूँ कि जनसंघ वाले क्या चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पूज्य गवर्नर हैं इन्होंने किसको कंसील किया? उनकी क्या पावर है हाउस के सामने

सी0एम0 हमारा है जिसको हम इलैक्ट करते हैं। यह बाहर का आदमी बेचारा उसमें क्या कर सकता है? (विघन) जनसंघ वाले और अपोजीशन वाले क्या मांगते हैं, उसके लिए तो यदि आप मुझे टाईम देंगे तो बोलूंगा और मुझे बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि ओर कोई बोलेगा नहीं। हिन्दुस्तान भर में रूज्जत पसन्द ताकतें हैं। जो इन्दिरा का इमेज इलैक्शन के बाद बना है, उसके साथ बंसी को जोड़ करके तमाम रूज्जत पसंद ताकतें इंदिरा के इमेज को, सोशलिज्म के इमेज को डिफीट देने के लिए कोशिश कर रही है और करैक्टर असैसिनेशन उसका एक पार्ट है। मैं डे-टु-डे स्टेटवाइज बातें गिना सकता हूँ कि वे किस तरह से होती आ रही है लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज किए देता हूँ कि अगर जनसंघ वाले यह चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो तो बंसी लाल की जुडीशियल इंक्वायरी तो इलेक्शन में हो चुकी। इलैक्टड आदमी की चाहे वह सरदार प्रताप सिंह कैरों हो या करुणानिधि हो, चाहे गुरनाम सिंह हो या बंसी लाल हो, प्रोविंशियल ओटोनोमी खत्म हो जाएगी अगर स्टेट करप्शन के नाम पर अपनी गाड़ी सेंटर को पकड़ा दे। मैं करुणानिधि के साथ हंड्रैड परसेंट एग्री करता हूँ कि सेंटर को कोई हक नहीं है किसी भी इलैक्टड सी0एम0 के खिलाफ सैन्ट्रल इंक्वायरी होल्ड करे लेकिन फिर भी, जहां तक बंसी लाल का ताल्लुक है, उनकी इंक्वायरी तो होगई। इंक्वायरी करने वाले चार आदमी थे। उनके बारे में यह कहना कि सारे ही बेईमान हैं और हम ही ईमानदार हैं, ठीक बात नहीं है और मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जिस आदमी ने रिपोर्ट किया है वे मिस्टर

गोखले है। वे दो साल जज रहे हैं और उन्होंने जब जजी छोड़ी तो बड़े नखरे के साथ। मैं उन्हें जानता हूँ। वे प्राईम मिनिस्टर से नहीं डरते। वे अपनी राय, अपनी ओपिनियन जो उनकी समझ में आए ठोकर कर देते हैं। मैंने उनकी कई अप्वायटमेंट्स देखी है। मैं उनके करैक्टर से वाकिफ हूँ। वह आदमी जिसकी कलम से सुप्रीम कोर्ट के जजिज अप्वायट होते हैं, जो खुद जज रहा है, जो हर बात को अंडरस्टैंड करता है, समझता है उसने और दूसरे आदमियों ने तुम्हारे कहने पर 6 महीने टाईम वेस्ट किया और एक रिपोर्ट तैयार की। फिर यह कह देना कि गोखले जुडीशियल परसोनल नहीं है, यह जुडीशियल इंक्वायरी नहीं हैं, ठीक बात नहीं है। यह जुडीशियल इंक्वायरी नहीं तो क्या है?

**श्री अध्यक्ष:** दौलता साहब, समय हो गया है।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** बात तो जनाब रह ही गई।

**श्री अध्यक्ष:** आपको समय मिलेगा।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** थैंक यू।

**श्री अध्यक्ष:** सदन कल प्रातःकाल साढ़े नौ बजे तक स्थगित किया जाता है।

**1 P.M.**

(तत्पश्चात् सदन वीरवार दिनांक 8 मार्च 1973 के प्रातः 9:30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)